सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivahan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

# परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 60, नई दिल्ली । रविवार, 12 मई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र


आज का सुविचार

जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते।


03 '10 साल हो गए सत्ता में, एक काम बता दें जो किया...
06 झारखंड में भ्रष्टाचार की असलियत
08 सामंजस्यपूर्ण शिक्षा: रिदमशाला छात्रों को संगीत से समृद्ध करती है


## लंबी दूरी के रूट पर चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें! बड़े पैमाने पर ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने की योजना

**भारतीय हाईवे पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी ! सरकार देश को ग्रीन मोबिलिटी (हरित गतिशीलता) में बदलने में तेजी लाने के अपनी कोशिशों के तहत लंबी दूरी के मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की तैयारी में है।**

संजय बांटला

**नई दिल्ली।** भारतीय हाईवे पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी ! सरकार देश को ग्रीन मोबिलिटी (हरित गतिशीलता) में बदलने में तेजी लाने के अपनी कोशिशों के तहत लंबी दूरी के मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की तैयारी में है। ताजा पहल का मकसद अंतरराज्यीय यात्री परिवहन है। अनुमानित 12.5 लाख से 14.5 लाख बसें इंटरसिटी या अंतरराज्यीय मार्गों पर संचालित होती हैं। जिनमें लगभग 2.5 लाख राज्य सरकार-नियंत्रित परिवहन उपयोगिताएं शामिल हैं।

इस समय डीजल पर चलने वाली, इलेक्ट्रिक बसों में बदलाव उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, ₹लंबे रूट पर इलेक्ट्रिक बसों की व्यवहार्यता आठ-नौ घंटे तक की निरंतर यात्रा के लिए स्थापित की गई है।₹ उन्होंने कहा कि ऐसी बसों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव पर विचार किया जा रहा है।

जबकि फेम इंडिया सब्सिडी योजना के तहत समर्थित इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल वर्तमान में शहर के परिवहन के लिए किया जाता है। लेकिन सरकार इसी तरह की सहायता योजना शुरू कर सकती है या अंतरराज्यीय परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए मौजूदा योजना का विस्तार कर सकती है।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, बड़े शहरी केंद्रों को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर फास्ट चार्जर सहित हाईवे पर ज्यादा चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित किया जाएगा।

अधिकारी ने बताया, ₹चार पहिया वाहनों (जैसे कार) के विपरीत लंबी दूरी के परिवहन की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसों में बड़ी और भारी बैटरी लगाई जा सकती हैं। क्योंकि चार्जिंग पर ज्यादा दूरी तय कर सकती हैं। ड्राइविंग रेंज से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रमुख रूट पर फास्ट-चार्जिंग बुनियादी ढांचे को भी बढ़ाया जाएगा।

सरकार जल्द ही लंबी दूरी के संचालन के लिए राज्य सरकारों द्वारा इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का समर्थन करने के लिए एक रोडमैप विकसित करेगी। इसके अलावा, निजी बस फ्लीट ऑपरेटरों और स्कूलों और कॉलेजों जैसे संस्थागत खरीदारों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने के उपायों पर विचार किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा, ₹स्कूलों की बसें शहरों के भीतर नियंत्रित दूरी पर दिन में मुश्किल से चार घंटे चलती हैं। उन्हें बिजली पर स्विच करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ई-बसों को अपनाने के लिए ज्यादा निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपायों पर विचार किया जा रहा है।

## इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर अपनाने से लागत और कार्बन में कैसे हो सकती है कटौती

परिवहन विशेष न्यूज

**पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरों में बदलाव, सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में तेजी से बढ़ रहा है। जानें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को अपनाने से लागत और कार्बन में कैसे कटौती हो सकती है।**

**नई दिल्ली।** पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरों में बदलाव, सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी (स्थायी शहरी गतिशीलता) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में तेजी से बढ़ रहा है। आर्थिक और पर्यावरणीय फायदों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर परिवहन के भविष्य को बदल रहे हैं।

2020 में, भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 168 प्रतिशत की असाधारण बढ़ोतरी देखी गई। जैसा कि ईवी मार्केट पर आईबीईएफ रिपोर्ट बताती है, जो एक मजबूत बढ़ते बाजार के रुझान को दर्शाता है। यह बदलाव सरकारी प्रोत्साहन, परिचालन लागत-दक्षता और पर्यावरणीय फायदों के कंबिनेशन से समर्थित है।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर 50,000 रुपये से 1,50,000 रुपये तक की कीमतों के साथ आते हैं। FAME-II जैसी सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी इन वाहनों को खरीदने में ग्राहकों को कुछ सहूलियत देती हैं। और उन्हें उपभोक्ताओं के व्यापक दायरे के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बनाती है। FAME-II योजना विशेष रूप से खरीदारों को वित्तीय लाभ प्रदान करती है। जो इन वाहनों की अग्रिम लागत को कम कर सकती है।

ई2वी की लागत-दक्षता उनके सबसे आकर्षक गुणों में से एक है। इन वाहनों के परिचालन लागत ईंधन से चलने वाले वाहनों की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत कम हैं। यह मुख्य रूप से पेट्रोल की तुलना में बिजली की कम लागत और इलेक्ट्रिक इंजन की उच्च दक्षता के कारण है।

इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन परिषद (ICCT) के अध्ययन में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि कम चलने वाले पार्ट्स और कम टूट-फूट के कारण, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के पूरे लाइफटाइम में रखरखाव की लागत काफी कम आती है।

पर्यावरण के नजरिए से भी, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के फायदे उतने ही आकर्षक हैं। E2W शून्य टेलपाइप उत्सर्जन करते हैं। जो पेट्रोल से चलने वाले टू-व्हीलरों द्वारा छोड़े गए प्रदूषकों की तुलना में बहुत अलग और बेहतर है। आईसीसीटी कहता है कि एक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लाइफटाइम में, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लगभग 11 पेड़ लगाने के बराबर होती है। कार्बन फुटप्रिंट में यह उल्लेखनीय कमी वायु गुणवत्ता के मुद्दों से जूझ रहे शहरों और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के वैश्विक प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है।

ओनरशिप की कुल लागत का आकलन करते समय, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर अपने पेट्रोल समकक्षों की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत कम लागत पेश करते हैं। इस अनुमान में न सिर्फ खरीद मूल्य और ईंधन लागत को, बल्कि वाहन की लंबी लाइफ के साथ-साथ रखरखाव खर्च को भी ध्यान में रखा गया है। ऐसी बचत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को न सिर्फ पर्यावरण के नजरिए से सही विकल्प बनाती है। बल्कि आर्थिक रूप से भी स्मार्ट ऑप्शन बनाती है।

इलेक्ट्रिक वाहनों में मोटरें इंटरनल कंब्शन इंजनों की तुलना में मूल रूप से कहीं ज्यादा एफिशिएंट होती हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने में लगभग 90 प्रतिशत कुशल होता है। जबकि ज्यादातर गैसोलीन इंजनों के लिए एफिशिएंसी लगभग 20-30 प्रतिशत होती है। इस हाई एफिशिएंसी (दक्षता) का मतलब है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर समान दूरी तय करने के लिए कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं।

## चारधाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन में जाम का झाम, मसूरी में भयानक ट्रैफिक से पर्यटक परेशान

परिवहन विशेष न्यूज

**मसूरी जाम में फंसे पर्यटकों का कहना है कि मसूरी में लगातार जाम लगने के कारण लोग काफी परेशान हैं। जाम से निपटने के लिए बनाए गए प्लान ध्वस्त हो गए हैं।**

**मसूरी:** पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन और यात्रा सीजन शुरू होते ही ट्रैफिक जाम की समस्या शुरू हो गई है। जाम से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से बनाई गई योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। मसूरी में षनिवार को सुबह से ही कई किलोमीटर का लम्बा जाम लगता रहा वही वाहन रेंगते हुए नजर आये। जिससे देष विदेष से मसूरी आये पर्यटक और चारधाम यात्रा जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू हो गया है। मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिसकी वजह से यहां पर खासा जाम देखने को मिल रहा है।स्थानीय पुलिस प्रशासन लोगों को जाम से निजात दिलाने में फेल होता नजर आ रहा है। यहां के कई इलाकों में जाम की वजह से पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये हाल तब है जब कुछ दिन पहले ही मसूरी में पर्यटन सीजन की तैयारियों और जाम से निपटने के लिए एसडीएम मसूरी द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर एक्शन प्लान तैयार किया गया था।

मसूरी में ज्यादातर मुख्य चौराहों पर जाम लग रहा है। मालरोड में सड़क किनारे वाहनों को पार्क किया जा रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी गांधी के मुख्य चौराहे गांधी चौक से पेट्रोल पंप पर लगातार जाम लग रहा है, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक जाने में काफी समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी में दो किलोमीटर का सफर दो घंटे में भी तय नही कर पा रहे है। पूरा दिन जाम में फंसे रहे के कारण उनको भारी दिक्कत पेश आई।

### प्रशासन के सारे दावे फेल

उन्होंने कहा कि मसूरी पेट्रोल पंप से गांधी चौक तक सड़क किनारे टूटे पुल के निर्माण का कार्य चल रहा है तो मसूरी गांधी चौक से जीरो प्वाइंट तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर टाइल लगाने का कार्य किया जा रहा है जिस कारण भी जाम की समस्या आ रही है। परन्तु जो कार्य पर्यटन और यात्रा सीजन से पहले होना था वह काम अब शुरू किये गए है । उन्होंने कहा कि पर्यटन और यात्रा सीजन को लेकर सरकार और प्रशासन की सारी योजनाएं ध्वस्त होती नजर आ रही है।

### मसूरी गांधी चौक से कैम्पटी तक जाम

मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी का कहना है कि मसूरी में अत्यधिक भीड़ होने के कारण मसूरी गांधी चौक से पेट्रोल पंप तक जाम की समस्या आ रही है। उन्होंने कहा कि मसूरी गांधी चौक से कैम्पटी जाने वाला मार्ग काफी संकरा है। इन दिनो मार्ग पर टाइल लगाने का कार्य चल रहा है जो जाम लगने का मुख्य कारण है। पुलिस द्वारा जाम से निजात दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा मसूरी के मुख्य चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है जिससे जाम की स्थिति पैदा ना हो वही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

## अतिक्रमण की दुविधा: प्रवर्तन एजेंसियां पीछे क्यों हैं?

परिवहन विशेष न्यूज

**नई दिल्ली।** शहरी परिदृश्य के क्षेत्र में, अतिक्रमण एक तेजी से व्यापक मुद्दा बन गया है, जिसकी प्रवृत्ति फुटपाथों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों तक फैली हुई है। हालांकि सड़क सुरक्षा पर अतिक्रमण के हानिकारक प्रभावों से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया अक्सर अपर्याप्त दिखाई देती है, जिससे कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि ऐसे उल्लंघन क्यों बने रहते हैं।

### अतिक्रमण की स्वीकृति:

अतिक्रमण की स्वीकृति को असंख्य परस्पर जुड़े कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो सामाजिक मानदंडों और प्रणालीगत कमियों दोनों में निहित हैं। कई क्षेत्रों में, पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी, जैसे कि निर्दिष्ट पार्किंग स्थान या पैदल यात्री पथ, अतिक्रमण व्यवहार के सामान्यीकरण में योगदान करते हैं। दुर्लभ प्रवर्तन संसाधन और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएँ समस्या को और बढ़ा देती हैं, जिससे अपराधियों में दण्ड से मुक्ति की भावना पैदा होती है।

इसके अलावा, सामाजिक-आर्थिक असमानताएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अक्सर अपर्याप्त शहरी नियोजन और प्रवर्तन का खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन क्षेत्रों में जहां बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सीमित है, अतिक्रमण को एक विकल्प के बजाय एक आवश्यकता के रूप में देखा जा सकता है, जो व्यक्तिगत नियंत्रण से परे परिस्थितियों से प्रेरित है। इस प्रकार, अतिक्रमण को संबोधित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो ऐसे व्यवहारों को कायम रखने वाले अंतर्निहित सामाजिक-आर्थिक कारकों को स्वीकार करता है और उनका समाधान करता है।

### पिछड़ रही प्रवर्तन एजेंसियां:

अतिक्रमण को संबोधित करने में प्रवर्तन एजेंसियों की कथित शिथिलता संसाधन बाधाओं, संस्थागत जड़ता और प्रणालीगत चुनौतियों के संयोजन से उत्पन्न होती है। अल्प वित्त पोषित और कम कर्मचारियों के कारण, कई प्रवर्तन एजेंसियां विशाल क्षेत्रों को कवर करने और असंख्य उल्लंघनों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, नौकरशाही बाधाएं और प्रक्रियात्मक अक्षमताएं प्रवर्तन प्रयासों को और बाधित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अतिक्रमण को संबोधित करने में देरी और विसंगतियां होती हैं।

इसके अलावा, प्रवर्तन गतिविधियों की प्राथमिकता अक्सर व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण और राजनीतिक विचारों को दर्शाती है। कुछ मामलों में, प्रवर्तन एजेंसियों को कुछ प्रकार के उल्लंघनों को दूसरों पर प्राथमिकता देने के दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे अतिक्रमण-संबंधी अपराधों की उपेक्षा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, अपराधियों और प्रवर्तन कर्मियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार और मिलीभगत प्रवर्तन प्रयासों की प्रभावकारिता को कमजोर करती है, सार्वजनिक विश्वास को खत्म करती है और दण्ड से मुक्ति की संस्कृति को कायम रखती है।

अतिक्रमण की दुविधा को हल करने के लिए सरकारी संस्थाओं, शहरी योजनाकारों, नागरिक समाज संगठनों और आम जनता सहित कई हितधारकों के ठोस प्रयास की आवश्यकता है। लक्षित आउटरीच और शिक्षा अभियानों के साथ बुनियादी ढांचे में सुधार में निवेश, सामाजिक मानदंडों को बदलने और सार्वजनिक स्थानों के लिए सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही, प्रवर्तन प्रथाओं में सुधार करना, पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार से मुकाबला करना प्रवर्तन एजेंसियों की प्रभावशीलता को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम हैं।

इसके अलावा, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और निवासियों और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना जमीनी स्तर पर अतिक्रमण से निपटने के प्रयासों को बढ़ा सकता है। मोबाइल रिपोर्टिंग ऐप्स और निगरानी प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, समुदाय अपने पड़ोस में अतिक्रमणकारी व्यवहारों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

अतिक्रमण की व्यापकता और प्रवर्तन एजेंसियों की कथित शिथिलता शहरी परिदृश्य को आकार देने वाले सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत कारकों की जटिल परस्पर क्रिया को रेखांकित करती है। अतिक्रमण के मूल कारणों को संबोधित करके और नवाचार, सहयोग और जवाबदेही के माध्यम से प्रवर्तन प्रयासों को पुनर्जीवित करके, समाज अपने सार्वजनिक स्थानों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और सुरक्षित, अधिक समावेशी समुदायों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

“**भाई साहब कहां नहीं है यह बताओ हर चौराहे पर अगर अभी यह एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा सही कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में यह सभी लोग 100 गज का प्लॉट मांगे और उसको बनाने के लिए सरकार से पैसे मांगेंगे** इस समय शहर में तीन एजेंसी की जिम्मेदारी है पहले एमसीएफ फिर एचएसबीपी फिर ट्रैफिक पुलिस जिला प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द जिस तरह से दिन प्रतिदिन हर चौराहे पर कई तरह की दुकान खोल जा रही हैं सभी विधानसभा में दिन प्रतिदिन यह बढ़ता जा रहा है इन सभी एनफोर्समेंट एजेंसी के अधिकारियों को हर वार्ड में देखना होगा खासकर एसजीएम नगर एनआईटी क्षेत्र सेक्टर 28 से लेकर अमृता हॉस्पिटल के दोनों साइड अकॉर्ड हॉस्पिटल से लेकर डीपीएस स्कूल बीपीटीपी चौक एवं सभी चौक सरकार के द्वारा सभी डिपार्टमेंट में इनको ठीक करने के लिए जवाब दे ही तय की हुई है समय सीमा तय की गई है मेरा निवेदन अधिकारियों से यही है कृपया थोड़ा देख लें वरना आने वाले समय में आप लोगों के लिए ही सिर दर्द दी यह बन जाएगा नेशनल हाईवे पर कई जगह बैंकट हॉल खुल गए हैं कहीं खुल रहे हैं जिनके पास कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है”

**सही फोरम पर समस्याओं को साझा करने के बाद, परिणाम दिखने लगे हैं, जैसा कि रोड सुरक्षा हरियाणा ग्रुप में कुछ समस्याओं को उजागर किया गया। निम्नलिखित राय दी गई है।**

एमसीएफ के सीईओ द्वारा की गई एक आश्चर्यजनक लेकिन आनंददायक कार्रवाई को साझा करना चाहूंगा। मैंने आज सुबह एक ईमेल लिखा था जिसमें सार्वजनिक शिकायतों या शिकायत पोर्टलों की अनुपलब्धता पर निराशा व्यक्त की गई थी (फरीदाद311 पहले से ही उपयोग में नहीं है) और गैर-कार्यक्षमता के बारे में एक शिकायत थी मेरे ब्लॉक में स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, मैडम ने तुरंत एमसीएफ अधिकारियों को मेरी शिकायत का समाधान करने का आदेश दिया और आधे घंटे के भीतर, मुझे एमसीएफ से एक इलेक्ट्रीशियन का फोन आया कि काम पूरा हो गया है, यह देखकर आश्चर्य हुआ ! इतनी तेज कार्रवाई कभी नहीं देखी। मैं सुश्री मोना जी की बहुत सराहना करता हूं। मेरी प्रशंसा, प्रशंसा और धन्यवाद। मैं इसे 'प्रवर्तन' के एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में उद्धृत कर सकता हूं !पोर्टल लॉन्च करने के संबंध में मेरी अन्य शिकायतें जल्द ही पूरी होंगी, यह देखने की मेरी उम्मीदें जीवित हैं। मैं इसके लिए उत्सुक हूं !

# देश में भ्रष्टाचार का खंड बन गया है झारखंड

भ्रष्टाचार के मामले सामने आने पर क्षेत्रीय दलों का प्रयास यही रहता रहा है कि इसे केंद्र की भाजपा सरकार की साजिश करार दिया जाए। कांग्रेस ने इन दलों के भ्रष्टाचार के मामलों में संरक्षक की भूमिका निभाई है।

गैरभाजपा राजनीतिक दलों के लिए देश में व्याप्त भ्रष्टाचार कोई चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है। यही वजह है कि खासतौर से क्षेत्रीय दलों की सरकारों में बेशर्मी से लूटने की होड़ मची हुई है। झारखंड में एक मंत्री के निजी सहायक के नौकर के घर से मिले करीब 35 करोड़ रुपए मिलने पर किसी भी दल ने कठोर कार्रवाई की मांग तो दूर बल्कि इस भारी-भरकम भ्रष्टाचार के लिए अफसोस तक जाहिर नहीं किया। यह पहला मौका नहीं है जब इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की असलियत उजागर हुई हो। इससे पहले भी असीम सुर्खियों में रहे भ्रष्टाचार के मामलों में भी क्षेत्रीय दलों की सत्तारुढ़ सरकारो के काले कारनामे सामने आ चुके हैं।

भ्रष्टाचार के मामले सामने आने पर क्षेत्रीय दलों का प्रयास यही रहता रहा है कि इसे केंद्र की भाजपा सरकार की साजिश करार दिया जाए। कांग्रेस ने इन दलों के भ्रष्टाचार के मामलों में संरक्षक की भूमिका निभाई है। कारण स्पष्ट है यदि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के भ्रष्टाचार के मामले उठाती है तो उसे अपनी गिरेबां में भी झाकना होगा। इससे ये दल एक-दूसरे के भ्रष्टाचार के मामलों में छिछालेदार करने लगेंगे। ऐसी हास्यादपद स्थिति से बचने के लिए ये दल एक-दूसरे के भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं करते हैं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मामलों में मौन साधे रखा है। यहां तक की कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार का जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझा। कांग्रेस को अंदाजा था कि इसका जिक्र करते ही भाजपा गठबंधन खिल्ली उड़ाने से चूकेगा नहीं। यही वजह रही कि कांग्रेस घोषणा पत्र में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर कोई वादा नहीं किया। आश्चर्य यह है कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहयोगी जहांगीर के यहां छापा मार कर प्रवर्तन निदेशालय ने 35 करोड़ रुपए बरामद किए। इस पर भी मंत्री आलम ने त्याग पत्र देना जरूरी नहीं समझा। झारखंड में सत्ता में शामिल कांग्रेस ने आलम के इस्तीफ की मांग तक नहीं की। अलबत्ता कांग्रेस ने इससे अपना दामन बचाने की कोशिश जरूर की। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित राहुल गांधी की सभा में मंच पर कांग्रेस कोटे से ग्रामीण विकास मंत्री बने आलमगीर आलम को जगह नहीं मिली। कांग्रेस ने आलमगीर को महज यह संदेश देकर औपचारिकता निभाई की पहले जांच से बरी होकर आओ।

इससे पहले झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन भी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। सोरेन को जमानत नहीं मिल सकी है। पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन 6 अक्टूबर 2023 को नई हेमंत सोरेन को कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि अक्सर होता है हर भ्रष्टाचारी ऐसे मामलों को फसाने की साजिश करार देता है, इसी तर्ज पर सोरेन ने भी आरोप से इनकार किया। कांग्रेस ने सोरेन की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे संघवाद के लिए झटका बताया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा था कि भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा लोकतंत्र को नष्ट करने का अभियान चला रही है।

कांग्रेस यह भूल गई कि पिछले साल दिसंबर में भी झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स ने 350 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश बरामद किया था। इस पर साहू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि छापेमारी में जो कैश बरामद किया गया है, वो मेरी शराब की कंपनियों का है। शराब का कारोबार नकदी में ही होता है और इसका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 290 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश मिला था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड के उनके ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान विभाग को अलमारी में करोड़ों रुपये भरे हुए मिले। धीरज साहू के पास कितना कैश बरामद हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार तीन दिन छापेमारी कर नोट गिनने पड़े। आलम ये रहा है कि नोट गिनने के लिए लाई गईं मशीनों की क्षमता कम पड़ गई। नोट गिनने के लिए तीन दर्जन मशीनों को मंगाया गया था, जो कम पड़ गईं। पीएम मोदी ने ओडिशा की रैली में किया नकद बरामदगी का जिक्र चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकद बरामदगी का जिक्र भी किया। उन्होंने केंद्र द्वारा जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए पूछा कि पड़ोसी राज्य झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं।

मोदी ने कहा कि अब आप ही बताइए, अगर मैं उनकी चोरी, उनकी कमाई, उनकी लूट बंद कर दूं, तो क्या वे मोदी को गाली देंगे या नहीं? गालियों के बावजूद, क्या मुझे आपका पैसा नहीं बचाना चाहिए। झारखंड और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। संयुक्त बिहार में ही झारखंड मे हुए चारा घोटाले से शुरू हुई थी और बड़े भ्रष्टाचार की कहानी आज भी बदस्तूर जारी है। चारा घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया था। इस घोटाले में पशुओं के चारे की चोरी की गई। 950 करोड़ के इस घोटाले मे 53 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि कुल 170 आरोपी बने गए थे। इस मामले का खुलासा 1996 में हुआ था। इसके बाद मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री काल मे शेल कंपनियों के जरिए काली कमाई को सफेद करने का मामला सामने आया। करीब 4 हजार करोड़ का ये घोटाले अपने आप मे देशभर के बड़े घोटालों में से एक था। आज भी मामला अदालत में है। मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जेल भी जाना पड़ा था। अलग झारखंड राज्य की मांग को अटल बिहारी वाजपेयी की तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2000 में पूरा तो कर दिया था। लेकिन जिस मकसद से अलग राज्य की मांग हो रही थी, वह मकसद पीछे छूट गया। झारखंड में लूट का सिलसिला शुरू हो गया। बिहार से अलग झारखंड बनाने की मांग इसलिए हो रही थी कि इसका समुचित विकास अपने ही संसाधनों से सुचारू ढंग से हो पाएगा। इसकी झलक भी पहले बजट में दिखी थी। राज्य सरकार का शुरुआती बजट सरप्लस था। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जिस विकास और खुशहाली का सपना लोगों ने देखा था, वह तो पूरा नहीं हुआ, उल्टे यहां लूट की संस्कृति दिन प्रतिदिन मजबूत होती गई। हाल के तीन साल में जिस तरह नौकरशाहों और नेताओं के घर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम नोटों का जखीरा बरामद करती आ रही है, उससे तो झारखंड का अघोषित नाम लूटखंड हो गया है।

गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी तीन दक्षिणी राज्यों तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मनी लॉनड्रिंग के आरोपों की भी जांच कर रही है। सभी नेताओं ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। क्षेत्रीय दल चाहे झारखंड का हो, दिल्ली, तमिलनाडू या फिर पश्चिमी बंगाल के, सब आकंठ तक भ्रष्टाचार के मामलों में डूबे हुए हैं। इन राज्यों के विपक्षी दलों के करीब एक दर्जन नेता जेलों में बंद हैं। इनमें से ज्यादातर की जमानत तक नहीं हो सकी है। इसी से विपक्षी दलों का यह आरोप कमजोर पड़ जाता है कि केंद्र में सत्तारुढ़ भाजपा जांच एजेंसियों को दुरुपयोग राजनीतिक रंजिश के कारण कर रही है। अभी तक किसी भी न्यायालय ने नेताओं के भ्रष्टाचार के भी मामले में यह निर्णय नहीं दिया कि केंद्रीय एजेंसियों ने दुर्भावनावश कार्रवाई की है। कांग्रेस इस मुद्दे पर मुंह इसलिए नहीं खोल सकती है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास और वर्तमान भी भ्रष्टाचार के आरोपों से रंगा हुआ है।

# भारत के टॉप न्यूट्रिशन संस्थान ने मिट्टी के बर्तनों को खाना पकाने के लिए सर्वश्रेष्ठ बर्तन घोषित किया, नॉन-स्टिक पैन के बारे में दी चेतावनी!

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (एनआईएन) ने भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशानिर्देशों को अपडेट किया है, जिसमें इसकी पर्यावरण-मित्रता और खाद्य संरक्षण गुणों के कारण खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों के उपयोग को सबसे सुरक्षित बताया गया है। एनआईएन धातु के बर्तनों में अम्लीय खाद्य पदार्थों के असुरक्षित भंडारण और नॉन-स्टिक पैन के अधिक गर्म होने के बारे में भी चेतावनी जारी करता है।

राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) ने हाल ही में ₹भारतीयों के लिए आहार दिशानिर्देश₹ को अपडेट किया। संशोधन में नई वैज्ञानिक खोजों, विकसित होती जीवनशैली, प्रचलित बीमारियों और खान-पान की बदलती आदतों को ध्यान में रखा गया है। एनआईएन के अनुसार खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों को सबसे सुरक्षित बर्तन बताया है और नॉन-स्टिक बर्तनों के बारे में चेतावनी दी है।

आपको बता दें कि, एनआईएन ने अपने दिशानिर्देशों में कहा कि मिट्टी के बर्तन सबसे सुरक्षित कुकवेयर हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं, भोजन तैयार करने के लिए कम तेल की आवश्यकता होती है और भोजन के पोषण को बरकरार रखता है। वहीं एनआईएन ने धातु, स्टील, नॉन-स्टिक पैन और ग्रेनाइट पत्थरों के उपयोग के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

**मेटल**

चटनी और सांबर जैसे एसिटिक एसिड खाद्य पदार्थों को एल्युमीनियम, लोहे, बिना लाइन वाले पीतल या तांबे के बर्तन में रखना असुरक्षित है।

**स्टेनलेस स्टील**

स्टेनलेस स्टील को आम तौर पर सुरक्षित माना जाता है, यह रिसाव नहीं करता है।

**नॉन-स्टिक पैन**

नॉन स्टिक पैन को यदि ताप 170°C से अधिक हो तो जोखिम। यदि कोटिंग घिस गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है तो उसे हटा दें।

**ग्रेनाइट पत्थर**

ग्रेनाइट पत्थर तब तक सुरक्षित माना जाता है जब तक इसमें टेफ्लॉन कोटिंग न हो। यदि हां, तो मध्यम-उच्च तापमान उचित है।

**रोजाना 20-25 ग्राम चीनी खाएं**

आहार दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीयों को अब अपने दैनिक चीनी सेवन को 20-25 ग्राम तक सीमित करने की सलाह दी जाती है, जो लगभग एक चम्मच के बराबर है, क्योंकि यह चीनी प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देश प्रोटीन सप्लीमेंट के उपयोग को हतोत्साहित करते हैं और तेल की खपत में कमी की वकालत करते हैं। इसके अलावा, अद्यतन अनुशंसाएं एयर-फ्राइंग और ग्रेनाइट से लेपित कुकवेयर के उपयोग का समर्थन करती हैं।

एनआईएन ने पहली बार पैकेज्ड फूड लेबल की व्याख्या के लिए दिशानिर्देश भी पेश किए हैं।

**कम तेल में बनाएं खाना**

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने बुधवार को संशोधित दिशानिर्देशों का जारी किया। अपडेट दिशानिर्देशों का एक उल्लेखनीय सुझाव खाना पकाने के तेल पर निर्भरता कम करना और नट्स, तिलहन और समुद्री भोजन जैसे स्रोतों से आवश्यक फैटी एसिड प्राप्त करना है। इसके अलावा, अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत के प्रबंधन पर सलाह भी प्रदान की गई है।

**प्रोटीन पाउडर के सेवन करने से बचें**

संशोधित आहार दिशानिर्देश उनके लाभों और जोखिमों के बीच असमानता के कारण प्रोटीन की खुराक से बचने पर जोर देते हैं। अंडे, डेयरी दूध, सोयाबीन, मटर और चावल जैसी सामग्रियों से प्राप्त प्रोटीन पाउडर को नियमित सेवन से सावधान किया जाता है। दिशानिर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार समिति की अध्यक्ष डॉ. हेमलता आर ने अतिरिक्त शर्करा, गैर-कैलोरी मिठास और कृत्रिम योजक युक्त प्रोटीन पाउडर के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला, जो घातक हो सकते हैं।

# जानें क्या है हीटस्ट्रोक, गर्मियों में क्यों होते हैं इसके अधिक मामले

गर्मियों के मौसम में बाहर तापमान अधिक होता है। इस दौरान तापमान अधिक होने पर अमूमन शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए तापमान को सामान्य कर लेता है। डॉक्टर का कहना है कि 98.7 के स्तर पर ही अमूमन शरीर का तापमान होना चाहिए। अगर तापमान इससे अधिक होता है और मरीज को अन्य समस्याएं होने लगती हैं तो इसे हीट स्ट्रोक माना जाता है। हीट्सट्रोक पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर फरहान अहमद।

**मरीज को होती है ये समस्याएं**

हीट स्ट्रोक होने पर मरीज के शरीर में कई परिवर्तन देखने को मिलते है। कई बार मरीज को उल्टी, चक्कर आना, पसीना आना आम होता है। हीट स्ट्रोक में भी तीन स्तर होते हैं। बता दें कि मौसम बदलने पर शरीर खुद ही तापमान को मेंटेन करने की कोशिश करता है। गर्मियों के मौसम में कई बार हीट स्ट्रोक हो जाता है क्योंकि व्यक्ति अधिक समय तक धूप में रहता है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अच्छा काम नहीं होता है। इस कारण शरीर का तापमान अधिक हो जाता है।

**लू लगने के कारण जानें यहां**

गर्म हवाएं यहां काफी अधिक होता है। आमतौर पर एक व्यक्ति के शरीर का तापमान 25 डिग्री तक होना चाहिए वहीं बाहर 40 डिग्री से 50 डिग्री तक तापमान रहता है। ऐसे में शरीर का तापमान जब अधिक बढ़ने लगता है तो ये स्थिति घातक होती है। इससे बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय धूप से बचने के सभी उपाय करें, जैसे चश्मा लगाएं, सिर और आंख ढ़क कर रखें।

**लू लगने पर दिखते हैं ये लक्षण**

हीट स्ट्रोक से पहले हीट क्रैम्प होता है जिसमें सिर दर्द, प्यास अधिक लगना, हाथ पैरों में दर्द की शिकायत होती है। ये पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज हीट एग्जर्शन की होती है, जिसमें शरीर का तापमान अधिक हो जाता है। शरीर का तापमान 40 डिग्री के आसपास हो जाता है। इस दौरान मरीज को पसीने आते है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, पसीना भी निकलता है। इस स्टेज में मरीज को प्यास अधिक लगती है, मुंह सूखता है, सिरदर्द की शिकायत होती है। हीट स्ट्रोक होने पर मरीज को वॉमिटिंग और चक्कर आने की शिकायत मरीजों को होती है।

**डीहाइड्रेशन से कितना अलग है हीटस्ट्रोक**

आमतौर पर व्यक्ति को डीहाइड्रेशन की शिकायत कभी भी हो सकती है। वहीं हीटस्ट्रोक सिर्फ गर्मियों के मौके पर ही होता है। मगर डीहाइड्रेशन कभी भी हो सकता है। डीहाइड्रेशन के साथ हीटस्ट्रोक हो ये जरुरी नहीं है मगर हीटस्ट्रोक होने पर डीहाइड्रेशन जरुर होता है। डीहाइड्रेशन होने पर शरीर में पानी की कमी होती है। पानी की कमी होने पर ही शरीर का ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होता है। ऐसे में शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए।ट

**ऐसे बचें हीटस्ट्रोक से**

बिना वजह बाहर नहीं जाना चाहिए। जरुरत पड़ने पर बाहर जाने की स्थिति में गमछा, छाता, कैप आदि का उपयोग करें। बाहर जाएं तो अधिक से अधिक पानी पिएं। पानी के अलावा नारियल पानी, जूस पीना लाभदायक होता है। घर से बाहर निकलने से पहले सत्तू का सेवन करना भी उपयोगी होता है। हर स्थिति में खुद को हाइड्रेट करके रखना चाहिए। अधिक देर तक भी धूप के कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहिए। हीटस्ट्रोक आमतौर पर अधिक देर तक धूप में नहीं रहना चाहिए। गर्मियों के मौसम में अल्कोहल लेने से भी बचना चाहिए।

**ऐसे लें ट्रीटमेंट**

हीटस्ट्रोक और तीनों स्टेज में मरीज को तत्काल छाया में ले जाना चाहिए। धूप में मरीज को नहीं रखना चाहिए। मरीज के शरीर पर पानी का छिड़काव करना चाहिए। ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे मरीज के शरीर का तापमान थोड़ा कम हो जाए। इसके बाद मरीज को अस्पताल ले जाएं। मरीज के शरीर को ठंडा करने के लिए आईस बाथ, एसी में बैठाना, पंखा चलाना, स्पंज बाथ दिलाना आदि उपाय करने से भी लाभ होता है। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि इस समस्या को दूर करने के लिए सिर्फ डॉक्टर की मदद ही लेनी चाहिए और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दरअसल शरीर में पानी की अधिक कमी होने पर अधिक समय तक इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

# ICMR ने प्रोटीन सप्लीमेंट के खिलाफ चेतावनी दी, डैमेज हो सकती है किडनी

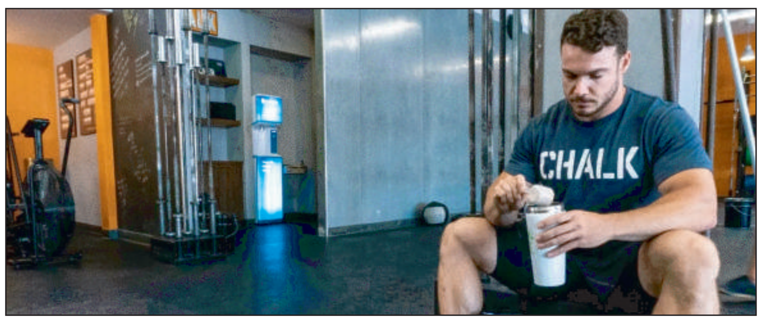


इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (एनआईएन) ने भारतीयों के लिए आहार दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें उन्होंने प्रोटीन सप्लीमेंट के सेवन पर प्रकाश डाला है जो आमतौर पर विशेष रूप से युवाओं के बीच में ज्यादा चलन में है।

148 पेज के दिशानिर्देशों में, आईसीएमआर ने बॉडी मास बढ़ाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट के सेवन के खिलाफ चेतावनी दी है, जो युवाओं द्वारा निर्धारित एक आम फिटनेस प्रवृत्ति है।

प्रोटीन की खुराक उन व्यक्तियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गई है जो अपने एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ाना चाहते हैं, मांसपेशियों के विकास में सहायता करना चाहते हैं, या अपनी दैनिक प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं।

**प्रोटीन पाउडर पर आईसीएमआर ने क्या दिशानिर्देश जारी किए**

यह Whey प्रोटीन पर जोर देता है, जो ब्रांच्ड-चेन अमीनो एसिड या बीसीएए में समृद्ध है। ये बीसीएए गैर-संचारी रोगों के उच्च जोखिम से जुड़े हैं।

ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलिन सहित ब्रांच्ड-चेन अमीनो एसिड (बीसीएए), प्रोटीन संश्लेषण, मांसपेशियों की मरम्मत और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मांसपेशियों की वृद्धि बढ़ाने, व्यायाम प्रदर्शन में सुधार और थकान को कम करने के लिए बीसीएए के साथ पूरक एथलीटों और बॉडीबिल्डरों के बीच लोकप्रिय है। शोध से पता चलता है कि बीसीएए यकृत रोग वाले व्यक्तियों को भी लाभ पहुंचा सकता है, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकता है और वजन घटाने में सहायता कर सकता है। हालांकि, इसके अत्यधिक सेवन से इंसुलिन प्रतिरोध और न्यूरोट्रांसमीटर संतुलन में व्यवधान जैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं।

हालांकि प्रोटीन सप्लीमेंट या प्रोटीन पाउडर सोयाबीन जैसे पौधे-आधारित स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन आईसीएमआर विपणन उद्देश्यों के लिए उनमें इस्तेमाल किए जाने वाले एडिटिव्स के खिलाफ चेतावनी देता है। अतिरिक्त शगुर, कृत्रिम मिठास और स्वाद प्रोटीन पाउडर से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ को कम कर देते हैं।

आईसीएमआर ने कहा है, 'अनाज का उचित संयोजनः 3:1 के अनुपात में दालें या प्रति दिन 80 ग्राम मांस के साथ 30 ग्राम अनुशंसित स्तर की दालों को शामिल करने से सामान्य व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोटीन की गुणवत्ता में सुधार होगा।'

**प्रोटीन सप्लीमेंट लेने पर क्या संभावित स्वास्थ्य जोखिम हो सकते है**

प्रोटीन सप्लीमेंट के सेवन से जुड़े अन्य संभावित स्वास्थ्य जोखिम क्या हैं? यहां जानें।

- अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन, किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। गुर्दे रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें यूरिया और अमोनिया जैसे प्रोटीन चयापचय के उप-उत्पाद भी शामिल हैं। उच्च प्रोटीन के सेवन से किडनी पर काम का बोझ बढ़ जाता है, जिससे समय के साथ किडनी खराब हो सकती है या उसकी शिथिलता हो सकती है, खासकर पहले से मौजूद किडनी की स्थिति वाले व्यक्तियों में।

- प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यूरिया का उत्पादन करता है, जो मूत्र में गुर्दे द्वारा उत्सर्जित होता है। अतिरिक्त यूरिया को बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है, जिससे मूत्र उत्पादन में वृद्धि होती है। यदि पर्याप्त जलयोजन बनाए नहीं रखा जाता है, तो अत्यधिक प्रोटीन का सेवन निर्जलीकरण में योगदान कर सकता है, जो समग्र स्वास्थ्य और एथलेटिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

-कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट, विशेष रूप से वे जिनमें Whey या कैसिइन प्रोटीन होता है, कुछ व्यक्तियों में पाचन संबंधी असुविधा जैसे सूजन, गैस, दस्त या कब्ज का कारण बन सकते हैं। ये लक्षण लैक्टोज असहिष्णुता, कुछ प्रोटीन स्रोतों के प्रति संवेदनशीलता, या कृत्रिम मिठास या गाढ़ेपन जैसे अतिरिक्त अवयवों की उपस्थिति के कारण हो सकते हैं।

# गर्मी में पाचन संबंधी समस्या से राहत पाने के लिए करें इस पानी का सेवन, चुटकियों में मिलेगा आराम

गर्मियों में पेट की समस्याएं बढ़ जाती हैं। पेट की समस्याओं से निजात पाने के लिए सौंफ का पानी रामबाण इलाज है। इसमें कई पाचनीय गुण पाए जाते हैं। रोजाना सौंफ के पानी का सेवन करने से कई पेट संबंधी समस्याओं से निजात पा सकते हैं।

गर्मियों में पेट की समस्याएं बढ़ जाती हैं। पेट की समस्याओं से निजात पाने के लिए सौंफ का पानी रामबाण इलाज है। इसमें कई पाचनीय गुण पाए जाते हैं। यदि आप रोजाना सौंफ के पानी का सेवन करते हैं, तो गैस, कब्ज, तनाव और पेट दर्द की समस्या से राहत पा सकते हैं। बता दें कि सौंफ में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। साथ ही इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। जो आपके पाचन तंत्र को सुधारने में सहायक होता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए आपको सौंफ के पानी के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं।

**सौंफ का पानी**

सौंफ का पानी बनाने के लिए सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच सौंफ को 1 कप पानी में रातभर के लिए भिगो दें। फिर सुबह इसको 5 मिनट उबाल लें। जब यह हल्का ठंडा हो जाए, तब इसका सेवन करें

**पाचन में सुधार**

बता दें कि सौंफ में पाचन को सुधारने वाले गुण पाए जाते हैं। जो गैस, ब्लोटिंग, अपच और एसिडिटी की समस्या को कंट्रोल करता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण पेट की सूजन व अन्य पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है।

**ठीक होगी बदहजमी**

सौंफ के सेवन से बदहजमी की समस्या ठीक हो सकती है। पेट में बनने वाले गैस्ट्रिक एसिड की मात्रा को सौंफ का पानी कंट्रोल करने में मदद करता है।

**कब्ज होगी दूर**

इसके साथ ही सौंफ का पानी कब्ज की समस्या दूर करने में भी सहायक होता है। क्योंकि सौंफ में फाइबर की अधिक मात्रा पाई जाती है। सौंफ के बीज में फेन्कोन, एस्ट्रैगोल और एनेथोल पाए जाते हैं। जो कब्ज और डाइजेशन की समस्याओं को दूर करता है। ऐसे में जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, उनको दिन में एक बार सौंफ का पानी अवश्य पीना चाहिए।

# '10 साल हो गए सत्ता में, एक काम बता दें जो किया...', रोड शो में केजरीवाल ने भाजपा से पूछे सवाल

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुबह को अपनी पत्नी सुनीता और पंजाब सीएम व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान जी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यालय में संबोधित किया। इसके बाद शाम को उन्होंने दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट में रोड शो किया। अब वह पूर्वी दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं।

**नई दिल्ली।** जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए रोड शो कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट में सहीराम पहलवान के लिए वोट मांगे। अब वो पूर्वी दिल्ली के कुलदीप कुमार के लिए रोड शो कर रहे हैं। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हैं।

**लोगों से पूछा हाल**

अरविंद केजरीवाल पूर्वी दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैसे हैं आप लोग, मेरी याद आई या नहीं? मुझे जेल में बहुत चिंता हो रही थी आप लोगों की। मुझे तो इन लोगों ने इंसुलिन तक नहीं दी। इन लोगों को 10 साल हो गए सत्ता में। एक काम तो बता दें कि इन्होंने क्या किया?

4 जून को अब यह सरकार रिपीट नहीं होगी। गठबंधन की सरकार बनेगी। आप भी हिस्सेदार होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। एलजी भी अपना होगा।

**'मुझे जेल से बाहर आए 20 घंटे हो गए हैं'**

केजरीवाल ने आगे कहा कि मुझे जेल से बाहर आए 20 घंटे हो गए हैं। मैंने कई लोगों से फोन पर बात की है। हर कोई कह रहा है कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है। हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक में उनकी सीटें कम हो रही हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी में इनका सफाया हो जाएगा, 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही है, 4 जून को भारत गठबंधन की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी।

**मेरी इंसुलिन बंद कर दी**

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चार जून को मोदी सरकार नहीं बनेगी। गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने जेल में 15 दिन के लिए मेरी शुगर की दवाई बंद कर दी। केजरीवाल ने कहा कि देश से तानाशाही को उखाड़ कर फेंकना होगा। इसलिए गठबंधन को वोट करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में भाजपा का सूपड़ा साफ हो रहा है।

**केजरीवाल कर रहे रोड शो**

अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए रोड शो कर रहे हैं। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हैं। वो महरौली में रोड शो कर रहे हैं। वह दक्षिण दिल्ली से गठबंधन प्रत्याशी सहीराम पहलवान के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रोड शो में काफी लोग मौजूद हैं।

**मोदी खतरनाक मिशन चालू कर रखा है: केजरीवाल**

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वन नेशन वन लीडर नामक खतरनाक मिशन चालू रख रखा है। वह विपक्ष के सारे नेता को निपटा देंगे और उनकी राजनीति खत्म कर देंगे। आज वह विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेज दिया। उत्तर से दक्षिण तक के कई नेताओं को जेल में बंद कर दिया है।

उन्हों ने कहा कि अगर ये चुनाव जीत गए तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ को दो महीने में निपटा देंगे। ये शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, वसुंधरा राजे का करियर खत्म कर दिया। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव जेल में होंगे।

उन्होंने कहा कि ये तानाशाह देश के सभी नेताओं को खत्म कर देंगे। इसलिए मैं आज आपसे भीख मांगने के लिए आया हूं कि मेरे देश को बचा लो। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे 20 दिन दिए हैं। मैं देश में बचाने के लिए पूरे देश का भ्रमण करूंगा।

**भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई मुझसे सीखें: केजरीवाल**

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ना है तो केजरीवाल से सीखो। एक बार मेरे हाथ एक ऑडियो हाथ लगी। एक मंत्री किसी दुकानवाले से 5 लाख रुपये मांग रहा था। ये बात किसी विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था। मैंने उसे पार्टी से निकाल दिया। इसी तरह पंजाब का एक मंत्री भी इसी भ्रष्टाचार में शामिल था। मैंने उसे पार्टी से निकाल दिया।

**बजरंगबली की कृपा की वजह से आज आपके बीच: केजरीवाल**

सीएम केजरीवाल ने कहा- सीधा जेल से आपके बीच में आ रहा हूं। आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है। 50 दिन बाद मैं, पत्नी और मान साहब के साथ सीपी के हनुमान मंदिर गया। बजरंगबली की खूब कृपा है हमारे ऊपर। उन्हीं की कृपा की वजह से आज आपके बीच में हूं।

**केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं सोच हैं: भगवंत**

केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को बंद कर दोगे, लेकिन उनकी सोच को कैसे बंद करोगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के सिर्फ 20 दिन बचे हैं। हमें अब 12 घंटे नहीं बल्कि 18 घंटे काम करना है। केजरीवाल के साथ जो कुछ हुआ, उसे पूरा देश देख रहा है। उन्होंने नारा भी पढ़ा- बीजेपी का हुआ बुरा हाल, बाहर आ गए केजरीवाल। उन्होंने कहाकि केजरीवाल कभी आउट नहीं हुए थे, बल्कि वह रिटायर्ड हर्ट हुए थे।

**केजरीवाल ने नवग्रह की भी पूजा की**

दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सीपी के मंदिर में नवग्रह की भी पूजा की।

**'कल कहा था आज आ गए केजरीवाल'**

आतिशी ने केजरीवाल के मंदिर दर्शन को लेकर कहा कि कल, जेल से बाहर आने के बाद, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह आशीर्वाद लेने के लिए यहां हनुमान मंदिर आएंगे। आज, वह अपने परिवार और अन्य पार्टी नेताओं के साथ यहां आ रहे हैं। कुछ दिन पहले सुनीता केजरीवाल हनुमान मंदिर आईं थीं और उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि वह जल्द ही अरविंद केजरीवाल के साथ यहां आएंगी।

**ये एक चमत्कार जो हनुमान जी की कृपा से हुआ**

मंदिर पहुंचे सौरभ भारद्वाज ने कहा, जब अरविंद केजरीवाल को झूठे मामले में जेल में डाल दिया गया था, तब सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि वह अरविंद केजरीवाल के साथ यहां हनुमान मंदिर आएंगी... उन्हें पीएमएलए कोर्ट में 50 दिनों में जमानत मिल गई, जो एक चमत्कार है और ऐसा हो सकता है हनुमान जी की कृपा से।

**मंदिर दर्शन कर बाहर निकले केजरीवाल**

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर दर्शन कर बाहर निकले।

**केजरीवाल ने मंदिर पहुंच की पूजा**

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता और पंजाब सीएम भगवंत मान समेत हनुमान मंदिर में की पूजा।

**मंदिर के बाहर और अंदर कार्यकर्ताओं-मीडिया का भारी जमावड़ा**

केजरीवाल के साथ में पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मंदिर के बाहर और अंदर कार्यकर्ताओं और मीडिया का भारी जमवाड़ा है।

**केजरीवाल से पहले मंदिर पहुंचे गोपाल राय**

दिल्ली के सीएम केजरीवाल के हनुमान मंदिर पहुंचने से पहले मंत्री गोपाल राय ने यहां पहुंचकर भगवान के दर्शन किए।

**सीपी के लिए घर से रवाना हुए केजरीवाल**

सीपी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के लिए केजरीवाल अपने आवास से निकले। थोड़ी देर में मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। यहां से पार्टी कार्यालय में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

## तिहाड़ से बाहर आते ही एक्शन में सीएम केजरीवाल, सभी विधायकों की बुलाई बैठक; इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

सीएम अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को अंतरिम जमानत पर रिहा हो गए। वहीं अब केजरीवाल ने अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। यह बैठक सीएम आवास पर रविवार सुबह होगी। इसमें आप के सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि सीएम केजरीवाल अपने सभी विधायकों के साथ चुनाव सहित सरकार की विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा कर सकते हैं।

**नई दिल्ली।** दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद हरकत में आ गए हैं। शनिवार सुबह उन्होंने पहले कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर गए, फिर दोपहर को उन्होंने पार्टी कार्यालय में प्रेस को संबोधित किया। इसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इसमें उन्होंने कई दावे भी किए, जिसमें अगले दो महीने में यूपी को सीएम पद से हटाने का बयान प्रमुख है। इसी बीच, सीएम केजरीवाल ने अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। यह बैठक सीएम आवास पर रविवार सुबह होगी। इसमें आप के सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि सीएम केजरीवाल अपने सभी विधायकों के साथ लोकसभा चुनाव सहित सरकार की विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा कर सकते हैं। यह बैठक सिविल लाइंस स्थित आवास पर होगी। बता दें, केजरीवाल के जेल में होने के कारण कई सरकार के कई काम रूके हुए थे और कई फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे थे। हालांकि वह बहुत जरूरी होने पर ही फाइलों पर साइन कर पाएंगे।

**भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी पर हमला**

बता दें, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर पीएम मोदी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े चोर, उच्चकों और डकैतों को अपनी पार्टी में इकट्ठा किया है और कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मोदी जी, अगर आपको भ्रष्टाचार से लड़ना सीखना है तो अरविंद केजरीवाल से सीखो। भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल ने लड़ाई लड़ी है। हमने भ्रष्टाचार के मामले में अपने मंत्रियों को भी नहीं छोड़ा है। विपक्ष और मीडिया को ना मालूम होते हुए भी उन्हें जेल भेज दिया।

## केजरीवाल ने रैली में भरी हुंकार, 4 जून को मोदी नहीं इंडी गठबंधन की बनेगी सरकार; पढ़िए भाषण की प्रमुख बातें

सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगले साल सितंबर में पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे और उनके नियम के मुताबिक वह रिटायर हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी कई ऐसे नेताओं को रिटायर किया था। आइए जानते हैं कि उन्होंने जेल से निकलने के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच से क्या-क्या बातें कही

**नई दिल्ली।** दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद शनिवार को आप कार्यालय में प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यहां तक बोला कि अगले साल सितंबर में पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे और उनके नियम के मुताबिक वह रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई ऐसे नेताओं को रिटायर किया था। आइए पढ़ते हैं उनके भाषण की प्रमुख बातें: किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच मैं बाहर आ पाऊंगा, लेकिन आप लोगों की दुआओं और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज मैं आप सबके बीच में हूं। आम आदमी पार्टी जैसी एक छोटी सी पार्टी को कुचलने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारे 4 टॉप लीडर को जेल में डाल दिया, उनको लगा था कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन AAP सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक सोच है, जितना ये खत्म करेंगे, उतनी ही हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े चोर, उच्चकों और डकैतों को अपनी पार्टी में इकठ्ठा किया है और कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको भ्रष्टाचार से लड़ना सीखना है तो अरविंद केजरीवाल से सीखो।

## भाजपा ने जेल में 15 दिन के लिए मेरी शुगर की दवाई बंद कर दी, रोड शो में बोले केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए पहला रोड शो कर रहे हैं। वह शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने रोड शो में कहा कि चार जून को भाजपा की मोदी सरकार नहीं बन रही है। भाजपा ने जेल में 15 दिन के लिए मेरी शुगर की दवाई बंद कर दी।

**नई दिल्ली।** आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए पहला रोड शो कर रहे हैं। वह शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। उन्होंने रोड शो में कहा कि चार जून को भाजपा की मोदी सरकार नहीं बन रही है।

**'मेरी इंसुलिन बंद कर दी'**

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चार जून को देश में गठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने जेल में 15 दिन के लिए मेरी शुगर की दवाई बंद कर दी। केजरीवाल ने कहा कि देश से तानाशाही को उखाड़ कर फेंकना होगा। इसलिए गठबंधन को वोट करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में भाजपा का सूपड़ा साफ हो रहा है।

**'मुझे जेल से बाहर आए 20 घंटे हो गए हैं'**

केजरीवाल ने आगे कहा कि मुझे जेल से बाहर आए 20 घंटे हो गए हैं। मैंने कई लोगों से फोन पर बात की है। हर कोई कह रहा है कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है। हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक में उनकी सीटें कम हो रही हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी में इनका सफाया हो जाएगा, 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही है, 4 जून को भारत गठबंधन की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी।

अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात कह कर भाषण खत्म कर दिया। वह दक्षिणी दिल्ली से गठबंधन प्रत्याशी सहीराम पहलवान के बारे में बोलना भूल गए। सहीराम की पहलवान की गाड़ी उनके पीछे थी। कुछ देर बाद उन्हें जानकारी दी गई। तब उन्होंने दोबारा माइक लेकर सहीराम पहलवान के लिए मतदान करने की अपील की।

**क्या बोले भगवंत मान**

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 25 मई को भाजपा सरकार गई। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने देश की दिशा और दशा दोनों बदल दिए हैं। वह भविष्य में देश का नेतृत्व करेंगे।

## 'हाथी' बिगाड़ सकता है दिल्ली का समीकरण, आप के बागी बीएसपी से ठोक रहे ताल; राजकुमार के बाद इस नेता पर सबकी नजर

**बसपा के दिल्ली के रण में आने के बाद मुकाबला कड़ा हो गया। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के आप छोड़कर बसपा के टिकट से नई दिल्ली सीट से और आप से बगावत कर पूर्वी दिल्ली से मोहम्मद वकार चौधरी के चुनाव मैदान में उतरने से पार्टी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दिल्ली में भाजपा और आइएनडीआइ (आप व कांग्रेस) के बीच आमने-सामने की लड़ाई है।**

बसपा के दिल्ली के रण में आने के बाद मुकाबला कड़ा हो गया। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के आप छोड़कर बसपा के टिकट से नई दिल्ली सीट से और आप से बगावत कर पूर्वी दिल्ली से मोहम्मद वकार चौधरी के चुनाव मैदान में उतरने से पार्टी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दिल्ली में भाजपा और आइएनडीआइ (आप व कांग्रेस) के बीच आमने-सामने की लड़ाई है।

**नई दिल्ली।** दिल्ली की चुनावी राजनीति से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का पुराना रिश्ता है। वर्ष 1989 से वह लोकसभा और विधानसभा के साथ ही नगर निगम चुनाव में वह अपना प्रत्याशी उतारती रही है। अब तक वह उसे लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली है, परंतु विधानसभा व निगम चुनाव जीतने में वह सफल रही है।

इस बार सभी सातों सीटों पर उसके प्रत्याशी खम ठोक रहे हैं। दिल्ली में लगभग 1.52 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से करीब 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति से संबंधित है। बसपा की नजर इनके साथ मुस्लिम मतदाताओं पर है।

**मोहम्मद वकार चौधरी पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी**

दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के आप छोड़कर बसपा के टिकट से नई दिल्ली सीट से और आप से बगावत कर पूर्वी दिल्ली से मोहम्मद वकार चौधरी के चुनाव मैदान में उतरने से पार्टी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दिल्ली में भाजपा और आइएनडीआइ (आप व कांग्रेस) के बीच आमने-सामने की लड़ाई है।

बसपा प्रत्याशियों के प्रदर्शन में सुधार होने से भाजपा व आइएनडीआइ प्रत्याशियों का चुनावी समीकरण बदल सकता है। बसपा नेताओं का कहना है कि दिल्ली में पार्टी की वर्षों से आधार है। संस्थापक कांशी राम पूर्वी दिल्ली से 1989 और 1991 से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पार्टी प्रमुख मायावती भी त्रिलोकपुरी में रह चुकी हैं।

**बसपा का दिल्ली में चुनावी इतिहास**

वर्ष 2014 में पार्टी सभी सातों संसदीय सीटों पर बसपा प्रत्याशी उतरे थे, किसी की जमानत नहीं बची। सबसे अधिक उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर 2.1 प्रतिशत मत मिले थे।

वर्ष 2019 में बसपा ने पांच उम्मीदवार उतारे थे और सभी की जमानत जब्त हो गई थी। सबसे अधिक उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2.6 प्रतिशत मत मिले थे।

दिल्ली की चुनावी राजनीति में उसका अबतक का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन 2008 के दिल्ली विधानसभा में रहा था। उसके दो प्रत्याशी विजयी हुए थे और छह सीटों पर वह दूसरे स्थान पर रहे थे।

नगर निगम चुनाव में बसपा ने 2007 में 17, 2012 में 15 और 2017 में तीन वार्डों में जीत मिली थी। वर्ष 2022 के निगम चुनाव में एक भी वार्ड में जीत नहीं मिली।

**बसपा एक आंदोलन है: लक्ष्मण सिंह**

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह का कहना है कि बसपा एक आंदोलन है। पिछले कुछ वर्षों से हमारा प्रदर्शन अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहा है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। दिल्ली में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अनुसूचित जाति पर ध्यान नहीं दिया। यह भ्रम फैलाया गया है कि दिल्ली में भाजपा को सिर्फ आम आदमी पार्टी हरा सकती है। इस कारण भाजपा व कांग्रेस से नाराज बहुजन समाज आप को अपना समर्थन दे रहे थे। अब आप ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है जिससे बहुजन समाज और मुस्लिम नाराज हैं। इनका समर्थन इस बार बसपा प्रत्याशियों को मिलेगा।

**बसपा के उम्मीदवार**

नई दिल्ली- राज कुमार आनंद
चांदनी चौक- अबुल कलाम आजाद
उत्तर पूर्वी दिल्ली- डॉ. अशोक कुमार
पूर्वी दिल्ली- मोहम्मद वकार चौधरी
उत्तर पश्चिमी दिल्ली- विजय बौद्ध
पश्चिमी दिल्ली- विशाखा आनंद
दक्षिणी दिल्ली- अब्दुल बासित

## ईएसआईसी अस्पताल के हजारो कर्मचारी 8 से 11 मई तक लंबित पडी मांगों पर करेगें विरोध प्रदर्शन

बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए शर्त रखी है कि वह अपने ऊपर चल रहे केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वह इसका माखौल उड़ाते हुए कह रहे हैं उनके ऊपर झूठा केस दर्ज हुआ है। यह सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। अदालत बड़े अपराधियों को भी छोड़ते समय लाइव लोकेशन शेयर करने को नहीं कहती है।

**नई दिल्ली।** भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल ने जिस तरह की राजनीति की है, वह देश के लिए घातक साबित हुआ है। प्रयोगवादी राजनीति का दौर अब समाप्त हो गया है। देश को जांचे परखे नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ नेतृत्व पर विश्वास है। देश में फिर से राष्ट्रवादी सरकार बनेगी।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल भी स्वीकार कर रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वह प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के नाम तो बता रहे हैं, लेकिन जेल जाने के बाद अपनी पार्टी के किसी नेता को उत्तराधिकारी नहीं बना सके।

**केस के बारे में टिप्पणी नहीं करने का आदेश**

प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए शर्त रखी है कि वह अपने ऊपर चल रहे केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वह इसका माखौल उड़ाते हुए कह रहे हैं उनके ऊपर झूठा केस दर्ज हुआ है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना है। अदालत बड़े अपराधियों को भी पैरोल पर छोड़ते समय लाइव लोकेशन शेयर करने को नहीं कहती है। लेकिन, केजरीवाल को लाइव लोकेशन शेयर करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल भारत की राजनीति में मूल्यों को ध्वस्त करने के सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे हैं। जेल से बाहर आने के बाद वह भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं और अपने इंडी गठबंधन के सदस्यों को आइना दिखाना शुरू कर दिया है। उन्हें अंतरिम जमानत मिलने का पाकिस्तान में स्वागत किया जा रहा है।

**आप नेताओं ने केजरीवाल की तानाशाही के बारे में कहा**

उन्होंने कहा कि आप छोड़ने वाले नेताओं ने केजरीवाल की तानाशाही के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कुछ कहा है। उन्हें अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है इसलिए जेल जाने पर उन्होंने स्टार प्रचारक की सूची में सबसे पहले अपनी पत्नी का नाम लिखवाया।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद हनुमान मंदिर में प्रार्थना करने के बाद प्रेसवार्ता की लेकिन एक बार भी उनके मुख से भगवान श्री राम का नाम नहीं निकला। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल की सोच भ्रष्टाचार की जननी है। इस सोच ने दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी बनाया और आबकारी घोटाले सहित कई घोटाले किए।

# नोएडावासी के लिए जरूरी खबर, सेक्टर 31 से 18 तक बंद हुई एलिवेटेड रोड; पढ़ें डायवर्जन रूट

सेक्टर 31 से 18 तक सरफेसिंग का काम होने के कारण एलिवेटेड रोड को बंद कर दिया गया है। सेक्टर–67/ थाना फेस–3 की ओर से एलिवेटेड मार्ग का प्रयोग कर सेक्टर–18 की ओर जाने वाले वाहन सेक्टर 60 अंडरपास के ऊपर से लेफ्ट टर्न कर एमपी 3 मार्ग होशियारपुर सिटी सेंटर सेक्टर 37/बोटेनिकल गार्डन से अपने गंतव्य की ओर जा सकेगे।

**नोएडा।** एलिवेटेड रोड पर नोएडा प्राधिकरण की ओर से चौथे चरण में सेक्टर-31-25 से सेक्टर-18 तक री सरफेसिंग का काम होगा, जिससे मार्ग पर वाहनों का प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर सेक्टर-60 से सेक्टर-33 इस्कॉन मंदिर लूप तक एलिवेटेड मार्ग खोल दिया गया है। इससे एलिवेटेड के एक हिस्सा पर वाहन फर्राटा भरने लगे हैं। इससे शाप्रिक्स मॉल, एआरटीओ कार्यालय, इस्कॉन मंदिर के पास ट्रैफिक जाम कम होने की उम्मीद है।

**ऐसा रहेगा यातायात**

- सेक्टर-33 इस्कान मंदिर से सेक्टर-31.25 चौक होकर सेक्टर-18, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे की ओर जाने वाला यातायात सेक्टर-35 मोरना होकर एमपी 3 मार्ग से अपने गंतव्य को जा सकेगा।
- सेक्टर-33 इस्कान मंदिर से सेक्टर-31.25 चौक होकर सेक्टर-18, चिल्ला/डीएनडी की ओर जाने वाला यातायात सेक्टर-31-25 चौक से पूर्व यूटर्न कर एडोब चौक से स्टेडियम चौक होकर एमपी-1 मार्ग से अपने गंतव्य को जा सकेगा।
- सेक्टर-67/ थाना फेस-3 की ओर से एलिवेटेड मार्ग का प्रयोग कर सेक्टर-18 की ओर जाने वाले वाहन सेक्टर 60 अंडरपास के ऊपर से लेफ्ट टर्न कर, एमपी 3 मार्ग होशियारपुर, सिटी सेंटर, सेक्टर 37/बोटेनिकल गार्डन से अपने गंतव्य की ओर जा सकेगे।
- सेक्टर-62/मॉडल टाउन, एनएच-24 की ओर से एलिवेटेड मार्ग का प्रयोग कर सेक्टर-18 की ओर जाने वाले वाहन सेक्टर-60 अंडरपास से होकर, सेक्टर-71/52 होते हुए एमपी-3 मार्ग होशियारपुर, सिटी सेंटर, सेक्टर 37/बोटनिकल गार्डन का प्रयोग कर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे।
- सेक्टर-71 की ओर से एलिवेटेड मार्ग का प्रयोग कर सेक्टर-18 की ओर जाने वाले वाहन सेक्टर-52 मेट्रो होते हुए एमपी-3 मार्ग होशियारपुर, सिटी सेंटर, सेक्टर-37/ बोटेनिकल गार्डन) का प्रयोग कर अपने गंतव्य की ओर जा सकेगे।
- किसान चौक, पर्थला की ओर से एलिवेटेड मार्ग का प्रयोग कर सेक्टर-18 की ओर जाने वाले वाहन सेक्टर-71 अंडरपास होकर एमपी 3 मार्ग होशियारपुर, सिटी सेंटर, सेक्टर-37/बोटेनिकल गार्डन का प्रयोग कर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे।

## RBI ने आर लक्ष्मी कंठ राव को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया, संभालेंगे ये जिम्मेदारियां

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आर लक्ष्मी कंठ राव को तत्काल प्रभाव से कार्यकारी निदेशक (ED) नियुक्त किया है। राव ED के तौर पर प्रमोट होने से पहले राव डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन में चीफ जनरल मैनेजर–इन–चार्ज के तौर पर काम कर रहे थे। राव ने बैंक व NBFC रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ बैंक्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसे क्षेत्रों में काम किया है।

**मुंबई।** रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आर लक्ष्मी कंठ राव को तत्काल प्रभाव से कार्यकारी निदेशक (ED) नियुक्त किया है। राव ED के तौर पर प्रमोट होने से पहले राव डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन में चीफ जनरल मैनेजर-इन-चार्ज के तौर पर काम कर रहे थे।

**तीन साल से आरबीआई के साथ**

राव के पास रिजर्व बैंक में तीन साल तक काम करने का अनुभव है। उन्होंने बैंक व NBFC रेगुलेशन, सुपरविजन ऑफ बैंक्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसे क्षेत्रों में काम किया है।

राव ने आरबीआई चेन्नई में बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में भी काम किया था। वह कई कमेटी और वर्किंग ग्रुप के मेंबर के रूप में भी काम कर चुके हैं। राव नीति निर्माण में योगदान देते रहे हैं।

राव बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, राइट टु इंफॉर्मेशन एक्ट (FAA), डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन को देखेंगे।

**कौन हैं लक्ष्मी कंठ राव**

राव के पास कॉमर्स में ग्रेजुएट डिग्री है। उनके पास श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (फाइनेंस) में मास्टर डिग्री और TIRM (IIBF) में डिप्लोमा है। वह IIBF के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं।

## पेट्रोल पंप पर कार में लगी आग, कर्मियों की सजगता से टला बड़ा हादसा

पेट्रोल पंप कर्मियों की सजगता से शनिवार को एक बड़ा हादसा होने से बच गया। अगर कर्मियों का कुछ मिनट बाद ध्यान जाता तो शायद बड़े हादसे हो सकता था। शनिवार दोपहर करीब दो बजे मदनपुरी रोड स्थित लक्ष्मी बाजार के सामने पेट्रोल पंप पर समसपुर निवासी विकास रेनाल्ट कंपनी की डैटसन गाड़ी में पेट्रोल डलवाने आए थे।

**गुरुग्राम।** पेट्रोल पंप कर्मियों की सजगता से शनिवार को एक बड़ा हादसा होने से बच गया। अगर कर्मियों का कुछ मिनट बाद ध्यान जाता तो शायद बड़े हादसे हो सकता था। शनिवार दोपहर करीब दो बजे मदनपुरी रोड स्थित लक्ष्मी बाजार के सामने पेट्रोल पंप पर समसपुर निवासी विकास रेनाल्ट कंपनी की डैटसन गाड़ी में पेट्रोल डलवाने आए थे। पेट्रोल डलवाने के दौरान कार के बोनट से धुआं निकल रहा था। तभी एक कर्मी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने तुरंत ही अपने अन्य साथियों

के साथ मिलकर कार को धक्का देकर पंप के बाहर रोड पर ले आए।

**टायरों में लगी आग**

कार जैसे ही पंप से बाहर रोड पर पहुंची तो देखते-देखते कार में लग गई। कार के साइड में खड़ी रेनाल्ट की काइगर कार भी आग की चपेट में आ गई। काइगर गाड़ी के दो टायरों में आग लग गई।

कर्मियों ने पेट्रोल पंप पर रखे अग्निशमन यंत्र से आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। उन्होंने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने चंद मिनट में आग पर काबू पा लिया।

## CNG वाहन चालक ध्यान दें! बढ़ती गर्मी को लेकर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; जरूर करें पालन

बढ़ती गर्मी को लेकर सीएनजी वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सीएनजी वाहन चालक प्रत्येक तीन साल के अंतराल में सीएनजी सिलेंडर की हाइड्रों टेस्टिंग (सरकार की गाइडलाइन के अनुसार) कराएं। सीएनजी वाहन चालक वाहन चलाते समय विषेश रुप से धुमपान न करें। चालक अपने वाहन में अग्निशमन यंत्र रखें। ये यंत्र चालू हालत में होने चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किए जा सके।

**फरीदाबाद।** अब तेज गर्मी पड़ने लगी है। इसे देखते हुए पुलिस ने सीएनजी वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अक्सर गर्मी में सीएनजी वाहनों में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। इससे बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और सुझाव भी साझा किए हैं।

**यह हैं सावधानियां**

सीएनजी वाहन चालक प्रत्येक तीन साल के अंतराल में सीएनजी सिलेंडर की हाइड्रों टेस्टिंग (सरकार की गाइडलाइन के अनुसार) कराएं। सीएनजी वाहन चालक वाहन चलाते समय विषेश रुप से धुमपान न करें। चालक अपने वाहन में अग्निशमन यंत्र रखें। ये यंत्र चालू हालत में होने चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किए जा सके। सीएनजी वाहन चालक अपने वाहन में वायरिंग को समय-समय पर चेक कराते रहें। कहीं कोई वायर, प्लग स्पार्क तो नही कर रहा।

**कंपनी फिटिड सीएनजी किट का प्रयोग करें**

चालक सदैव कंपनी फिटिड सीएनजी किट का प्रयोग करें। अलग से सीएनजी किट लगवाने से बचे। सीएनजी गैस रिसाव से बचाव के लिए सिलेंडर को समय-समय पर लीकेज टेस्ट कराएं। कंपनी की गाइडलाइंस के अनुसार गाड़ी का एयर फिल्टर प्रत्येक सीएनजी वाहन में 10 हजार किलोमीटर पर बदलवाना जरूरी होता है। सीएनजी वाहन में हमेशा सीएनजी किट वारंटी वाली व इंश्योरेंस के साथ प्रयोग करे।

अगर सीएनजी वाहन को चालक अधिक दूरी तक प्रयोग कर रहे हैं तो रास्ते में कुछ समय रुककर वाहन चलाएं। सीएनजी गाड़ी में सीएनजी डलवाते समय पंप पर धुपान न करें। गाडी को बंद कर दें। उतर कर ही सीएनजी डलवाएं। इलेक्ट्रोनिक उपकरण का प्रयोग न करें।

**सस्ती के चक्कर में बढ़ रहे सीएनजी वाहन**

दरअसल पेट्रोल-डीजल महंगा होने के कारण गाड़ियों में कम्प्रैस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) किट लगवाने वालों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि सीएनजी किट लगवाने के बाद क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आमतौर पर सीएनजी किट लगवाने के लिए लोग कम कीमत वाली किट को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे लोग चाइनीज किट लगवाते हैं। यह खराब रेटिंग के साथ आती है। इस किट को लोग सस्ते के चक्कर में लगवा लेते है।

**आग लगते ही लाक हो जाता है सिस्टम**

जब किसी कार में आग लगती है तो सबसे पहले कार में लगे इलेक्ट्रिकल यूनिट जाम हो जाते हैं। पावर विंडो, सीट बेल्ट और सेंट्रल लाकिंग सिस्टम तक फेल हो जाते हैं, जिसकी

वजह से कार में बैठे लोगों को बाहर निकलने में काफी दिक्कतें आती हैं।

**सीएनजी वाहन में आग की घटनाएं**

- 10 मार्च 2024 को हाईवे स्थित एनएचपीसी चौक पर एक कार की टक्कर से सीएनजी आटो में आग लग गई। आटो चालक फंस गया और बुरी तरह से झुलस गया।
- 22 जुलाई 2023 को बाटा मेट्रो स्टेशन के नीचे चलती सीएनजी कार में अचानक आग लग गई। कार में चालक सहित दो युवक सवार थे। समय रहते दोनों कार से बाहर आ गए।
- अगस्त 2023 में सैनिक कालोनी के सामने हरियाणा रोडवेज की सीएनजी बस में अचानक से आग लग गई। गनीमत रही कि वक्त रहते ही सारी सवारियां बस से नीचे उतर गई।

# अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के सियासी मायने को ऐसे समझिए

**सुप्रीम कोर्ट के एक साहसिक निर्णय से जेल में बंद भारतीय राजनेताओं के चुनावों के दौरान बाहर आने और चुनाव प्रचार में अपनी भागीदारी जताने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। समझा जाता है कि कोर्ट के इस उदार पहल से भारत में एक नई सियासी क्रांति का आगाज हो सकता है।**

मृत्युंजय दीक्षित

सुप्रीम कोर्ट के एक साहसिक निर्णय से जेल में बंद भारतीय राजनेताओं के चुनावों के दौरान बाहर आने और चुनाव प्रचार में अपनी भागीदारी जताने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। समझा जाता है कि कोर्ट के इस उदार पहल से भारत में एक नई सियासी क्रांति का आगाज हो सकता है। लिहाजा, इस निर्णय के सफेद और स्याह पक्ष पर चर्चा करने से पहले यह बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे और पिछले 50 दिन से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आगामी एक जून 2024 तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।

ऐसा इसलिए कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में विगत 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी के इस निर्णय की तब बहुत आलोचना हुई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जो भारतीय राजनीतिक इतिहास की अनोखी घटना बन चुकी है। इसी मामले में गत 8 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान ही न्यायमूर्ति खन्ना ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। इससे एक दिन पहले भी यानी गत 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कहा था कि मामले की सुनवाई जल्दी पूरी होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में कोर्ट लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है।

हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी थी कि अगर चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो वह मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे और न ही किसी फ़ाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भिजवाने वाली ईडी परेशान हो गई। आनन-फानन में ईडी ने एक हलफनामा दायर करके उनके अंतरिम जमानत का विरोध किया और कुछ अकाट्य दलीलें भी दी। जिस पर केजरीवाल की लीगल टीम ने भी कड़ी आपत्ति जताई। जिसके दृष्टिगत सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।

यही वजह है कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलने के सियासी और न्यायिक मायने तलाशे जा रहे हैं। क्योंकि यह एक असाधारण न्यायिक आदेश है, जो अब बौद्धिक विमर्श का मुद्दा भी बन चुका है। समझा जा रहा है कि कोर्ट के ताजा निर्देश से जहां देश में जनतांत्रिक भावनाओं को बल मिलेगा, वहीं भ्रष्टाचार और अपराध में शामिल राजनेताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। क्योंकि जेल से बाहर रहने का एक अमोघ कानूनी हथियार कोर्ट के फैसले से उन्हें मिल चुका है। लिहाजा, आने वाले दिनों में जेल में बंद भारतीय राजनेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगे जाने के मामले बढ़ेंगे।

बता दें कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल को किसी भी तरह की विशेष राहत देकर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिया जाना समानता और कानून के शासन के लिए अभिशाप जैसा होगा। इससे ऐसी नजीर कायम होगी कि सभी अपराध करने वाले अनैतिक राजनेता चुनाव की आड़ में जांच को नजरअंदाज करेंगे, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, नगरपालिका चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर आम चुनाव। यदि वे गिरफ्तार किए जाते हैं तो प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगेंगे।

दो कदम आगे की सोचते हुए उसने तर्क दिया कि आजतक किसी भी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, चाहे जेल में बंद वह व्यक्ति स्वयं भी प्रत्याशी क्यों न रहा हो, जबकि केजरीवाल तो उम्मीदवार भी नहीं हैं। ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि अपराधी जेल से ही चुनाव लड़े और जीत भी गए, लेकिन उन्हें कभी इस आधार पर जमानत नहीं मिली। वैसे भी चुनाव प्रचार न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही मौलिक अधिकार। लिहाजा ऐसा

होने से कानून का उल्लंघन करने वाले हर अपराधी को राजनीतिज्ञ बनने और वर्ष भर प्रचार के मोड में रहने का प्रोत्साहन मिलेगा। राजनेता आम आदमी से ऊपर होने और विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता।

ईडी ने अपनी दलील में चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि मतदान का अधिकार, जिसे कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार माना है, वह भी हिरासत के दौरान नहीं रहता। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 62(5) जेल में बंद व्यक्ति के मतदान के अधिकार में कटौती की बात करती है। यह चीज देखने लायक है कि पिछले पांच सालों में करीब 123 चुनाव हुए हैं और अगर किसी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाने लगे तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार करके जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि चुनाव तो सालभर चलने वाली गतिविधि है। हर राजनीतिज्ञ हर स्तर पर यह दलील दे सकता है कि अगर उसे जमानत नहीं दी गई तो उसे न भरपाई होने वाला नुकसान होगा।

ईडी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस समय सिर्फ पीएमएलए कानून में ही बहुत से नेता जेल में हैं। उनके मामलों को जांचने के बाद सक्षम अथॉरिटी ने उनकी हिरासत को सही ठहराया है। बहुत से नेता पीएमएलए के अलावा अन्य अपराधों में जेल में होंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के साथ विशेष व्यवहार करने और उनकी विशेष मांग स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है।

उसने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल ने कई समन के बाद भी जांच एजेंसी के सामने पेश न होने के पीछे पांच राज्यों में चुनाव का यही आधार दिया था। ऐसे में अगर कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी तो उनके द्वारा आप के स्टार प्रचारक होने के आधार पर प्रचार के लिए समन को नजरअंदाज करने का कारण बनाये जाने पर न्यायिक मुहर लग जाएगी। साथ ही प्रचार के लिए अन्तरिम जमानत से प्रचार की इच्छा रखने वाले नेताओं का एक अलग वर्ग बन जायेगा।

हालांकि कोर्ट ने ईडी की एक न सुनी और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय लोकतंत्र को किंतु-परन्तु के आधार पर नहीं, बल्कि स्पष्ट और पारदर्शी नीतियों के आधार पर ही चलाया जाएगा। संभव है कि अगली संसद इससे सबक लेगी और नेताओं के लिए आवश्यक कानून बनाएगी या फिर पूर्व की विसंगतियों को दूर करेगी।

यह स्वाभाविक सवाल है कि जब चुनावी मौसम हो और दल विशेष का प्रमुख नेता ही जेल में हो तो उसकी पार्टी को सही जनादेश कैसे मिल पाएगा। शायद इसलिए कोर्ट ने अंतरिम जमानत की नई राह दिखा दी और सियासी नकेल अपने हाथों में रख ली।

# आसान नहीं है सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक कार बेचना, बाजार विकसित होने में लगेंगे कई साल

**कार डीलर्स भी अपने ग्राहकों को सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक कार के प्रति बहुत भरोसा नहीं दिला पाते हैं इसलिए वे सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक कार को बेचने में बहुत दिलचस्पी नहीं लेते हैं। डीलर्स कहते हैं कि यात्री कार की बिक्री में इलेक्ट्रिक कार की हिस्सेदारी सिर्फ दो प्रतिशत है और इसका बाजार सिर्फ पांच साल पुराना है। लोग पुरानी इलेक्ट्रिक कार को लेकर उत्साह नहीं दिखाते हैं।**

परिवहन विशेष न्यूज

**नई दिल्ली।** दीपक तनेजा ने अगस्त 2022 में टाटा नेक्सन एक्स जेड प्लस इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी यह सोच कर की थी कि वह इस कार से एक चार्ज में देहरादून की सफर तय कर लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। अब वह इस कार को बेचना चाहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कार होने के नाते इसे बेचना भी आसान नहीं दिख रहा है।

उन्होंने इस कार को 17.40 लाख रुपए (ऑन रोड प्राइस) में खरीदा था और मात्र डेढ़ साल पुरानी कार को पांच लाख कम दाम पर बेचने को तैयार है। यही कार अगर पेट्रोल डीजल की होती तो हाथोंहाथ बिक गई होती। सिर्फ तेनजा ही नहीं, उनके जैसे कई इलेक्ट्रिक कार मालिक अपनी कार बेचने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं।

**नहीं खरीदना चाहते पुरानी इलेक्ट्रिक कार**

कार डीलर्स भी अपने ग्राहकों को सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक कार के प्रति बहुत भरोसा नहीं दिला पाते हैं, इसलिए वे सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक कार को बेचने में बहुत दिलचस्पी नहीं लेते हैं। डीलर्स कहते हैं कि यात्री कार की बिक्री में इलेक्ट्रिक कार की हिस्सेदारी सिर्फ दो प्रतिशत है और इसका बाजार सिर्फ पांच साल पुराना है। शुरू के दो साल तो मुख्य रूप से टैक्सी या सरकारी ऑफिस में ही इलेक्ट्रिक कार चलाई जा रही थी।

इस साल अप्रैल में 3,35,123 यूनिट यात्री वाहन की बिक्री हुई और इनमें इलेक्ट्रिक कार की हिस्सेदारी 7,415 यूनिट की थी। वित्त वर्ष 2023-24 में 82,000 इलेक्ट्रिक कार की बिक्री हुई। दो साल पहले तो हिस्सेदारी और भी कम थी। सीमित उपलब्धता एवं जानकारी से लोग पुरानी इलेक्ट्रिक कार को लेकर उत्साह नहीं दिखाते हैं।

**ये है मुख्य वजह**

इसकी बैट्री को लेकर भी लोगों में संशय है। सोसायटी ऑफ मैन्यूफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) के महानिदेशक सोहिंदर सिंह गिल के मुताबिक इलेक्ट्रिक कार की कीमत में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी बैट्री की होती है और जैसे-जैसे बैट्री पुरानी होती है, उसकी क्षमता कम होती जाती है और इसका असर माइलेज पर भी दिखता है। इसलिए भी लोग पुरानी इलेक्ट्रिक कार लेने से कतराते हैं।

हालांकि इलेक्ट्रिक कार में बैट्री की गारंटी आठ साल की होती है, लेकिन अगर कोई चार साल पुरानी इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो चार साल बाद उसे नई बैट्री लेने के लिए नई कार की 40 प्रतिशत कीमत चुकानी होगी। पांच साल से अधिक पुरानी इलेक्ट्रिक कार तो ग्राहक बिल्कुल नहीं खरीदना चाहेगा। इन सब कारणों से ही सेकेंड हैंड कार बेचने वाली कंपनियां इलेक्ट्रिक कार की कोई गारंटी नहीं

लेती है जबकि पुरानी पेट्रोल-डीजल कार पर ये कंपनियां गारंटी-वारंटी देती है।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अकादमी एंड रिसर्च विंग के चेयरमैन वी. गुलाटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक कार की रिसेल अच्छी होने में अभी पांच साल लगेंगे और दुनिया भर में यही स्थिति है। उन्होंने बताया कि ईवी में ग्राहकों के पास विकल्प नहीं है, जहां डीजल-पेट्रोल कार में ग्राहक शो रूम में प्रवेश करते हैं तो उनके पास आठ-दस विकल्प होते हैं तो इलेक्ट्रिक कार में सिर्फ एक।

बैट्री और चार्जिंग सुविधा को लेकर ग्राहकों में अभी भरोसा नहीं जगा है। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स में एक इको-सिस्टम विकसित हो गया है, इसलिए पुराने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की बिक्री होने लगी है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर आनंद कुलकर्णी कहते हैं कि चार साल पहले ही इलेक्ट्रिक कार की शुरुआत हुई है, इसलिए अभी रिसेल मार्केट नहीं बन पाया है।

इलेक्ट्रिक कार के मालिकों ने बताया कि घर पर चार्ज करने पर उन्हें घरेलू बिजली दर के हिसाब से शुल्क देना पड़ता है, लेकिन हाईवे या अन्य सार्वजनिक जगहों पर चार्ज करने पर उन्हें 21 रुपए प्रति यूनिट प्लस जीएसटी के हिसाब से शुल्क चुकाना पड़ता है। चार्जिंग स्टेशन सभी जगहों पर उपलब्ध नहीं होने से भी इलेक्ट्रिक कार लोगों के जेहन में नहीं उतर पा रही है।

## टाटा नेक्सन को मिला नया पेट्रोल और डीजल बेस वेरिएंट, पहले से हुई 1.10 लाख रुपये सस्ती

**नेक्सन पेट्रोल को अब स्मार्ट (ओ) नाम से एक नया एंट्री-लेवल वेरिएंट दिया गया है जिसकी कीमत 8 लाख रुपये है। यह वेरिएंट पिछले बेस वेरिएंट यानी स्मार्ट से 15000 रुपये ज्यादा किफायती है। टाटा नेक्सन डीजल को दो नए वेरिएंट मिलते हैं - स्मार्ट + और स्मार्ट + एस। पहला नया एंट्री-लेवल वेरिएंट है जिसकी कीमत 10 लाख रुपये है जबकि बाद वाले की कीमत 10 .60 लाख रुपये है।**

**नई दिल्ली।** Mahindra XUV 3XO को हाल ही में किफायती कीमतों पर लॉन्च किए जाने के बाद Tata ने Nexon SUV की कीमतों में भी कटौती कर दी है। कंपनी ने Nexon के लिए नए बेस वेरिएंट लॉन्च किए हैं। अब इसकी शुरुआती कीमत 7.49 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है।

**Tata Nexon की घटी कीमतें**

नेक्सन पेट्रोल को अब स्मार्ट (ओ) नाम से एक नया एंट्री-लेवल वेरिएंट दिया गया है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपये है। यह वेरिएंट पिछले बेस वेरिएंट यानी स्मार्ट से 15,000 रुपये ज्यादा किफायती है। ऐसा लग रहा है कि नए वेरिएंट को XUV 3XO के निचले वेरिएंट को कंपीट करने के लिए पेश किया गया है, जिनकी कीमत 7.49 लाख रुपये है।

इसके अलावा स्मार्ट + और स्मार्ट + एस वेरिएंट की कीमतें क्रमशः 30,000 रुपये और 40,000 रुपये कम की गई हैं। Tata Nexon Smart+ की कीमत अब 8.90 लाख रुपये है, जबकि Smart+ S की कीमत 9.40 लाख रुपये है।

**डीजल वेरिएंट के नए प्राइस**

टाटा नेक्सन डीजल को दो नए वेरिएंट मिलते हैं - स्मार्ट + और स्मार्ट + एस। पहला नया एंट्री-लेवल वेरिएंट है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपये है, जबकि बाद वाले की कीमत 10.60 लाख रुपये है। नए वेरिएंट के आने से नेक्सॉन डीजल की बेस कीमत 1.10 लाख रुपये कम हो गई है।

**इंजन और परफॉर्मेंस**

कंपनी ने अपनी इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है। टाटा नेक्सॉन को 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 120hp और 170Nm और 1.5-लीटर डीजल यूनिट के साथ पेश करता है, जो 115hp और 260Nm टॉर्क पैदा करता है। ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड एएमटी और साथ ही 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक शामिल है। मार्च में इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को पांच नए ऑटोमैटिक वेरिएंट भी मिले थे।

## 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बेस वेरिएंट में मिलते हैं ये फीचर्स, जानिए कौन सा है वैल्यू फॉर मनी ट्रिम

**2024 Maruti Suzuki Swift के LXi ट्रिम की कीमत 6.49 लाख रुपये है और ये केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ बेचा जाएगा जबकि अन्य सभी ट्रिम्स एमटी या एएमटी के साथ खरीदे जा सकते हैं। कीमत कम रखने की वजह से ऐसा किया गया है। इसके VXi वेरिएंट को एमटी में 7.29 लाख रुपये और एएमटी में 7.79 लाख रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है।**

**नई दिल्ली।** 2024 Maruti Suzuki Swift का बेस LXi वेरिएंट हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED टेल लैंप, 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ESP, HHA, रिवर्सिंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, मैनुअल AC, कीलेस एंट्री, सेंट्रल लॉकिंग, फोर पावर विंडो, मैनुअली एडजस्टेबल विंग मिरर और एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट जैसे फीचर्स के साथ आता है।

**LXi वेरिएंट**

LXi ट्रिम की कीमत 6.49 लाख रुपये है और ये केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ बेचा जाएगा, जबकि अन्य सभी ट्रिम्स एमटी या एएमटी के साथ खरीदे जा सकते हैं। कीमत कम रखने की वजह से ऐसा किया गया है।

**VXi वेरिएंट**

इसके VXi वेरिएंट को एमटी में 7.29 लाख रुपये और एएमटी में 7.79 लाख रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस वेरिएंट में ओआरवीएम पर टर्न सिग्नल, फुल व्हील कवर, बॉडी कलर्ड ओआरवीएम और डोर हैंडल, पार्सल ट्रे, वॉयस असिस्टेंस के साथ 7 इंच की टचस्क्रीन, ओटीए अपडेट, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो इंटरफेस, ब्लूटूथ, यूएसबी टाइप-ए चार्जिंग मिलती है।

**VXi (O) वेरिएंट**

Vxi (O) की कीमत VXi वेरिएंट से 27,000 रुपये अधिक है। इसके लिए स्मार्ट की के साथ पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम और कनेक्टेड फीचर्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

**ZXI वेरिएंट**

ZXI वेरिएंट में आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, 15 इंच के अलॉय व्हील, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट 6 स्पीकर ऑडियो, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, रियर वाइपर और वॉशर, फॉलो-मी के साथ ऑटो हेडलैंप जैसे अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं।

**ZXi+ वेरिएंट**

इसके ZXi+ वेरिएंट में फ्रंट एलईडी फॉग लाइट्स, चमड़े से लिपटे स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट फुटवेल रोशनी, रियर पार्किंग कैमरा, 9 इंच का स्मार्टप्ले प्रो + टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, आर्कमिस ऑडियो और क्रूज कंट्रोल के साथ कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं।

# रॉयल एनफील्ड भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च करेगी 2 नई 350 सीसी बाइक, नई डिटेल्स आईं सामने

**रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जे-सीरीज इंजन प्लेटफॉर्म में ब्रांड के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2021 के अंत में बाजार में आने के बाद से इसे ग्राहकों से गर्मजोशी से स्वागत मिला है। जावा और येज्दी जैसे प्रतिस्पर्धी ब्रांड्स के लिए प्रतिस्पर्धी 300-350 सीसी बॉबर सेगमेंट में प्रवेश करने के लिए रॉयल एनफील्ड अपने मौजूदा क्लासिक मॉडल का एक अपडेटेड वर्जन पेश करने की तैयारी कर रहा है।**

**नई दिल्ली।** Royal Enfield चालू वित्त वर्ष में 350 सीसी, 450 सीसी और 650 सीसी सेगमेंट में नई पेशकशों के साथ अपनी मोटरसाइकिल लाइनअप का विस्तार करने के लिए तैयार है। इन अपडेट के बीच, लोकप्रिय क्लासिक रेंज में संशोधन किया जाएगा, जिसमें फ्रेस Classic 350 और एक संभावित बॉबर संस्करण की शुरूआत शामिल है। इसे भारतीय बाजार में Goan Classic 350 नाम दिए जाने की संभावना है।

**अपडेटेड RE Classic 350**

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, जे-सीरीज इंजन प्लेटफॉर्म में ब्रांड के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2021 के अंत में बाजार में आने के बाद से इसे ग्राहकों से गर्मजोशी से स्वागत मिला है। मीटियोर 350, बुलेट 350 और हंटर 350 जैसे मॉडलों के साथ क्लासिक 350 ने ब्रांड की बिक्री मात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक रेट्रो रोडस्टर मिड-लाइफ अपडेट प्राप्त करने में लाइनअप का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। अपेक्षित परिवर्तनों में समग्र आकर्षण को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं और ग्राफिक्स के साथ नई रंग योजनाओं की शुरूआत शामिल है। इसे मौजूदा 349 सीसी एसओएचसी एयर और ऑयल-कूल्ड इंजन के साथ ही पेश किया जाना रखा जाएगा। ये पावरट्रेन 20 एचपी से थोड़ा अधिक और 27 एनएम का टॉर्क देता है और इसे 5-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा रहेगा।

**Royal Enfield Goan Classic 350**

जावा और येज्दी जैसे प्रतिस्पर्धी ब्रांड्स के लिए प्रतिस्पर्धी 300-350 सीसी बॉबर सेगमेंट में प्रवेश करने के लिए, रॉयल एनफील्ड अपने मौजूदा क्लासिक मॉडल का एक अपडेटेड वर्जन पेश करने की तैयारी कर रहा है। इस सिंगल-सीट बॉबर वेरिएंट में स्टैंडर्ड क्लासिक मॉडल की तुलना में रेस्ड हैंडलबार, व्हाइटवॉल टायर और अपडेटेड एर्गोनॉमिक्स सहित महत्वपूर्ण बदलाव होंगे।

खबर है कि इसका नाम Goan Classic 350 रखा जाएगा, लेकिन आधिकारिक विवरण की अभी पुष्टि नहीं हुई है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका लॉन्च आने वाले महीनों में इस CY के बाद अपडेटेड क्लासिक 350 की रिलीज से पहले होगा, क्योंकि इसका डिजाइन पेटेंट पहले ही लीक हो चुका है।

# अप्रैल 2024 में रही सबसे ज्यादा इन 7-सीटर कारों की मांग, देखिए टॉप-10 गाड़ियों की लिस्ट

परिवहन विशेष न्यूज

**अप्रैल 2024 में टॉप-10 फैमिली कारों की बिक्री में महिंद्रा स्कॉर्पियो ने मारुति सुजुकी अर्टिगा महिंद्रा बोलेरो और टोयोटा इनोवा को पीछे छोड़ते हुए चार्ट में पहला स्थान हासिल किया है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और हाइक्रॉस की कुल बिक्री 7103 यूनिट की हुई जो 2023 में इसी अवधि के दौरान बेची गई 4837 इकाइयों की तुलना में 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।**

**नई दिल्ली।** इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा SUV बिकती हैं और 7-सीटर कारों की भा अच्छी-खासी मांग है। अपने इस लेख में हम आपके लिए पिछले महीनें बिकी टॉप-10 फैमिली कारों की लिस्ट लेकर आए हैं।

1. अप्रैल 2024 में टॉप-10 फैमिली कारों की बिक्री में महिंद्रा स्कॉर्पियो ने मारुति सुजुकी अर्टिगा, महिंद्रा बोलेरो और टोयोटा इनोवा को पीछे छोड़ते हुए चार्ट में पहला स्थान हासिल किया है। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने 14,807 इकाइयों की बिक्री का आंकड़ा छुआ है।

2. मारुति सुजुकी अर्टिगा सात-सीटर वॉल्यूम चार्ट में दूसरे स्थान पर रही, इसी अवधि के दौरान पिछले साल बेची गई 5,532 इकाइयों की तुलना में 145 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ 13,544 इकाइयों की बिक्री दर्ज की गई।

2023 की अवधि के दौरान, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन की कुल बिक्री 9,617 इकाई थी, जो साल-दर-साल 54 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत देती है।

3. तीसरे स्थान पर रहते हुए, बोलेरो ने अप्रैल 2024 में 9,537 इकाइयों की घरेलू रैली हासिल की है, जो पहले बेची गई 9054 इकाइयों की तुलना में 5 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि के साथ थी।

4. टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और हाइक्रॉस की कुल बिक्री 7,103 यूनिट की हुई, जो 2023 में इसी अवधि के दौरान बेची गई 4,837 इकाइयों की तुलना में 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

5. इस बीच, महिंद्रा एक्सयूवी700 ने पिछले महीने कुल 6,134 इकाइयों की बिक्री के साथ पांचवां स्थान हासिल किया। पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 4,757 इकाइयों की तुलना में साल-दर-साल बिक्री में 29 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

6. किआ कैरेंस 5,328 इकाइयों के साथ छठे स्थान पर रही, जो पिछले साल की समान अवधि में बेची गई 6,107 इकाइयों की तुलना में 13 प्रतिशत की गिरावट है।

7. क्रम में नीचे जाते हुए, मारुति सुजुकी XL6 ने अप्रैल 2023 में 2,860 इकाइयों के मुकाबले 3,509 इकाइयों की बिक्री के साथ 23 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की।

8. टोयोटा फॉर्च्यूनर की पिछले महीने 2,325 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि बारह महीने पहले इसी अवधि के दौरान 2,578 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। इस तरह सालाना बिक्री में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है।

9. टाटा सफारी 1,716 यूनिट की बिक्री के साथ नौवें स्थान पर रही, जो 2023 में इसी अवधि में बेची गई 2,029 इकाइयों की तुलना में 15 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाती है।

10. रेनो ट्राइबर 1,671 यूनिट की बिक्री के साथ टॉप-10 की लिस्ट में अंतिम स्थान पर है। वहीं, 2023 में इसी अवधि के दौरान 2,079 यूनिट की बिक्री हुई, जो सालाना स्तर पर 20 प्रतिशत गिरावट को दर्शाती है।

## इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी विकसित करने वाले IIT-मद्रास स्टार्टअप की आनंद महिंद्रा ने की सराहना

**नई दिल्ली।** महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी विकसित करने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास स्टार्टअप की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह संस्थान दुनिया के सबसे रोमांचक और सक्रिय इनक्यूबेटरों में से एक बन गया है।

**पोस्ट कर की तारीफ**

महिंद्रा ने एक्स पर पोस्ट किया कि अगले साल तक उड़ने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी बनाने के लिए आईआईटी मद्रास में एक कंपनी बनाई जा रही है। संस्था को धन्यवाद देते हुए, उन्होंने आगे कहा कि पूरे भारत में महत्वाकांक्षी इनक्यूबेटरों की तेजी से बढ़ती संख्या के साथ हमें अब ऐसे देश के रूप में नहीं देखा जाता है, जहां वास्तविक इनोवेटर्स की कमी है। महिंद्रा ने लिखा कि साहसिक आकांक्षाएं मायने रखती हैं। कोई सीमा स्वीकार न करें।

**यूजर्स ने की टिप्पणी**

शेयर किए जाने के बाद से उनकी पोस्ट को 190K से ज्यादा बार देखा जा चुका है। कई उपयोगकर्ताओं ने टिप्पणियों में अपने विचार भी साझा किए। एक उपयोगकर्ता ने लिखा, ₹रोमांचक समय, यह साहसी सोच जड़ें जमा रही है। हमारे विशाल प्रतिभा पूल और एक सहायक वातावरण के साथ, भारतीय नवप्रवर्तक वास्तव में उड़ान भर रहे हैं।

एक अन्य यूजर ने कहा कि भारत के इनक्यूबेटर भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, और आईआईटी मद्रास अपने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी प्रोजेक्ट के साथ इसका नेतृत्व कर रहा है। यह उस तरह का नवाचार है जो एक देश को मानचित्र पर रखता है और सपने देखने वालों और काम करने वालों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करता है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, आईआईटी मद्रास ने कहा कि उसने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अपने पूर्व छात्रों, उद्योग और व्यक्तिगत दाताओं से 513 करोड़ रुपये की सर्वकालिक उच्च राशि जुटाई। FY24 के दौरान पूर्व छात्र और कॉर्पोरेट भागीदार से संस्थान ने 717 करोड़ रुपये की कुल नई प्रतिज्ञाएं भी प्राप्त कीं।

# झारखंड में भ्रष्टाचार की असलियत

योगेंद्र योगी

**झारखंड में सत्ता में शामिल कांग्रेस ने आलम के इस्तीफे की मांग तक नहीं की। अलबत्ता कांग्रेस ने इससे अपना दामन बचाने की कोशिश जरूर की। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित राहुल गांधी की सभा में मंच पर कांग्रेस कोटे से ग्रामीण विकास मंत्री बने आलमगीर आलम को जगह नहीं मिली।**

इसी से विपक्षी दलों का यह आरोप कमजोर पड़ जाता है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक रंजिश के कारण कर रही है। अभी तक किसी भी न्यायालय ने नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले में यह निर्णय नहीं दिया कि केंद्रीय एजेंसियों ने दुर्भावनावश कार्रवाई की है'

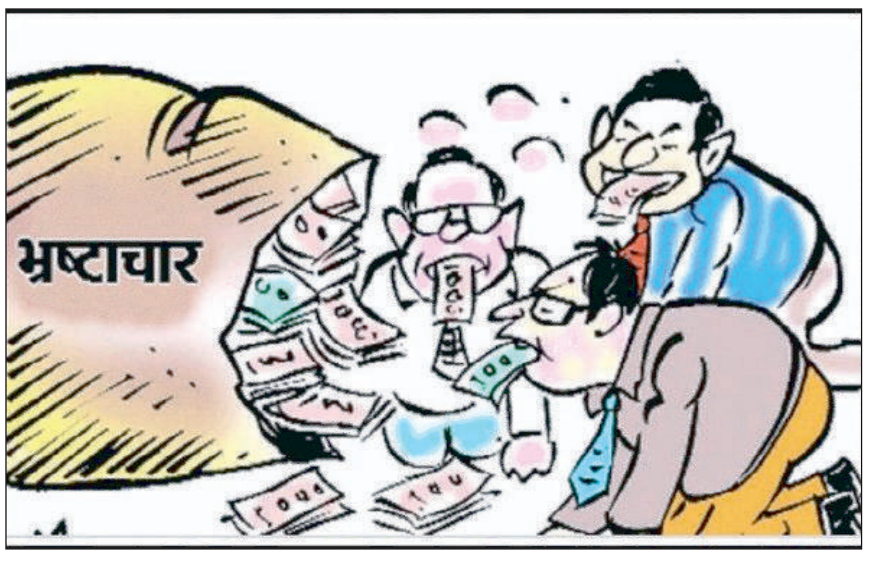


गैर भाजपा राजनीतिक दलों के लिए देश में व्याप्त भ्रष्टाचार कोई चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है। यही वजह है कि खास तौर से क्षेत्रीय दलों की सरकारों में बेशर्मी से लूटने की होड़ मची हुई है। झारखंड में एक मंत्री के निजी सहायक के नौकर के घर से करीब 35 करोड़ रुपए मिलने पर किसी भी दल ने कठोर कार्रवाई की मांग तो दूर, बल्कि इस भारी-भरकम भ्रष्टाचार के लिए अफसोस तक जाहिर नहीं किया। यह पहला मौका नहीं है जब इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की असलियत उजागर हुई हो। इससे पहले भी असीम सुर्खियों में रहे भ्रष्टाचार के मामलों में क्षेत्रीय दलों की सत्तारूढ़ सरकारों के काले कारनामे सामने आ चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामले सामने आने पर क्षेत्रीय दलों का प्रयास यही रहता रहा है कि इसे केंद्र की भाजपा सरकार की साजिश करार दिया जाए। कांग्रेस ने इन दलों के भ्रष्टाचार के मामलों में संरक्षक की भूमिका निभाई है। कारण स्पष्ट है यदि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के भ्रष्टाचार के मामले उठाती है तो उसे अपनी गिरेबां में भी झांकना होगा। इससे ये दल एक-दूसरे के भ्रष्टाचार के मामलों में छिछालेदार करने लगेंगे। ऐसी हास्यास्पद स्थिति से बचने के लिए ये दल एक-दूसरे के भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं करते हैं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मामलों में मौन साधे रखा है। यहां तक कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार का जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझा। कांग्रेस को अंदाजा था कि इसका जिक्र करते ही भाजपा गठबंधन खिल्ली उड़ाने से चूकेगा नहीं। यही वजह रही कि कांग्रेस घोषणा पत्र में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर कोई वादा नहीं किया। आश्चर्य यह है कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहयोगी जहांगीर के यहां छापा मार कर प्रवर्तन निदेशालय ने 35 करोड़ रुपए बरामद किए। इस पर भी मंत्री आलम ने त्यागपत्र देना जरूरी नहीं समझा।

झारखंड में सत्ता में शामिल कांग्रेस ने आलम के इस्तीफे की मांग तक नहीं की। अलबत्ता कांग्रेस ने इससे अपना दामन बचाने की कोशिश जरूर की। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित राहुल गांधी की सभा में मंच पर कांग्रेस कोटे से ग्रामीण विकास मंत्री बने आलमगीर आलम को जगह नहीं मिली। कांग्रेस ने आलमगीर को महज यह संदेश देकर औपचारिकता निभाई कि पहले जांच से बरी होकर आओ। इससे पहले झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। सोरेन को जमानत नहीं मिल सकी है। पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन 6 अक्टूबर 2023 को कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि अक्सर होता है, हर भ्रष्टाचारी ऐसे मामलों को फंसाने की साजिश करार देता है, इसी तर्ज पर सोरेन ने भी आरोप से इनकार किया। कांग्रेस ने सोरेन की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे संघवाद के लिए झटका बताया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा था कि भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा लोकतंत्र को नष्ट करने का अभियान चला रही है। कांग्रेस यह भूल गई कि पिछले साल दिसंबर में भी झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स ने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया था। इस पर साहू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि छापेमारी में जो कैश बरामद किया गया है, वो मेरी शराब की कंपनियों का है। शराब का कारोबार नकदी में ही होता है और इसका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 290 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड के उनके ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान विभाग को अलमारी में करोड़ों रुपए भरे हुए मिले। धीरज साहू के पास कितना कैश बरामद हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार तीन दिन छापेमारी कर नोट गिनने पड़े। आलम यह रहा कि नोट गिनने के लिए लाई गईं मशीनों की क्षमता कम पड़ गई। नोट गिनने के लिए तीन दर्जन मशीनों को मंगाया गया था, जो कम पड़ गईं। पीएम मोदी ने ओडिशा की रैली में नकद बरामदगी का जिक्र किया।

चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकद बरामदगी का जिक्र करते हुए, केंद्र द्वारा जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए पूछा कि पड़ोसी राज्य झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। मोदी ने कहा कि अब आप ही बताइए, अगर मैं उनकी चोरी, उनकी कमाई, उनकी लूट बंद कर दूं, तो क्या वे मोदी को गाली देंगे या नहीं? गालियों के बावजूद, क्या मुझे आपका पैसा नहीं बचाना चाहिए। झारखंड और भ्रष्टाचार का चोली-दामन का साथ है। संयुक्त बिहार में ही झारखंड में हुए चारा घोटाले से शुरू हुई थी और बड़े भ्रष्टाचार की कहानी आज भी बदस्तूर जारी है। चारा घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया था। इस घोटाले में पशुओं के चारे की चोरी की गई। 950 करोड़ के इस घोटाले में 53 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि कुल 170 आरोपी बने गए थे। इस मामले का खुलासा 1996 में हुआ था।

इसके बाद मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री काल में शेल कंपनियों के जरिए काली कमाई को सफेद करने का मामला सामने आया। करीब 4 हजार करोड़ का यह घोटाला अपने आप में देशभर के बड़े घोटालों में से एक था। आज भी मामला अदालत में है। मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जेल भी जाना पड़ा था। अलग झारखंड राज्य की मांग को अटल बिहारी वाजपेयी की तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2000 में पूरा तो कर दिया था, लेकिन जिस मकसद से अलग राज्य की मांग हो रही थी, वह मकसद पीछे छूट गया। झारखंड में लूट का सिलसिला शुरू हो गया। बिहार से अलग झारखंड बनाने की मांग इसलिए हो रही थी कि इसका समुचित विकास अपने ही संसाधनों से सुचारू ढंग से हो पाएगा। इसकी झलक भी पहले बजट में दिखी थी। राज्य सरकार का शुरुआती बजट सरप्लस था। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जिस विकास और खुशहाली का सपना लोगों ने देखा था, वह तो पूरा नहीं हुआ, उल्टे यहां लूट की संस्कृति दिन प्रतिदिन मजबूत होती गई।

हाल के तीन साल में जिस तरह नौकरशाहों और नेताओं के घर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम नोटों का जखीरा बरामद करती आ रही है, उससे तो झारखंड का अघोषित नाम लूटखंड हो गया है। गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी तीन दक्षिणी राज्यों तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की भी जांच कर रही है। सभी नेताओं ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। क्षेत्रीय दल चाहे झारखंड का हो, दिल्ली, तमिलनाडू या फिर पश्चिमी बंगाल के, सब आकंठ तक भ्रष्टाचार के मामलों में डूबे हुए हैं। इन राज्यों के विपक्षी दलों के करीब एक दर्जन नेता जेलों में बंद हैं। इनमें से ज्यादातर की जमानत तक नहीं हो सकी है। इसी से विपक्षी दलों का यह आरोप कमजोर पड़ जाता है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक रंजिश के कारण कर रही है। अभी तक किसी भी न्यायालय ने नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले में यह निर्णय नहीं दिया कि केंद्रीय एजेंसियों ने दुर्भावनावश कार्रवाई की है। कांग्रेस इस मुद्दे पर मुंह इसलिए नहीं खोल सकती है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास और वर्तमान भी भ्रष्टाचार के आरोपों से रंगा हुआ है।

## संपादक की कलम से

# अब हिंदू-मुस्लिम आबादी

आज भारत की जनसंख्या 144 करोड़ से अधिक है, जो विश्व में सर्वाधिक है। हालांकि 2021 में जनगणना नहीं की जा सकी, क्योंकि वह कोरोना वैश्विक महामारी का दौर था। जनगणना 2011 में की गई थी, उसके बाद 13 लंबे साल गुजर चुके हैं, लेकिन कोई अधिकृत जनगणना नहीं हुई है। 2011 में हिंदू आबादी 79.80 फीसदी थी, जबकि मुस्लिम आबादी 14.20 फीसदी थी। मुसलमानों की बढ़ोतरी दर करीब 25 फीसदी थी, जबकि हिंदुओं की बढ़ोतरी दर करीब 17 फीसदी थी। यानी हिंदुओं की तुलना में मुसलमान बढ़ रहे थे। आजादी के बाद 1951 में देश में करीब 3.5 करोड़ मुसलमान थे, जिनकी आबादी 2023 में बढ़ कर 20 करोड़ के पार हो गई। अब तो यह आंकड़ा भी बदल चुका होगा! गौरतलब तथ्य यह है कि 1951 से आज तक मुसलमानों की आबादी एक बार भी नहीं घटी, लगातार बढ़ती रही है। अब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रपट के जरिए चौंकाने वाले आंकड़े और रुझान सामने आए हैं। रपट में 1950 से 2015 तक जनसंख्या के रुझान के आंकड़े दिए गए हैं। ये इस कालखंड में जनगणना के दौरान भी सामने आए होंगे! तो फिर आर्थिक सलाहकार परिषद की ऐसी रपट तब क्यों सार्वजनिक की गई, जब आम चुनाव, 2024 के तीन चरण के मतदान सम्पन्न हो चुके हैं? लोकसभा की 282 सीटों, करीब 52 फीसदी, पर जनादेश ईवीएम में दर्ज हो चुका है। रपट के मुताबिक, 1950 से 2015 तक की 65 साल की अवधि में बहुसंख्यक हिंदू आबादी 84.68 फीसदी से घट कर 78.6 फीसदी हो गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 9.84 से बढ़ कर 14.09 फीसदी हो गई है। हिंदू करीब 8 फीसदी घटे हैं और मुसलमानों की बढ़ोतरी 43.15 फीसदी हुई है। आबादी का यह असंतुलन चुनौतीपूर्ण, खतरनाक, चिंताजनक और विस्फोटक हो सकता है! भारत इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, सर्बिया आदि देशों में आबादी के असंतुलन के कारण विभाजन देख चुका है। देश दोफाड़ हुए हैं और नए देश बने हैं। इंडोनेशिया कभी हिंदू, बौद्ध बहुल देश था, लेकिन आज दुनिया के सबसे अधिक मुसलमान इंडोनेशिया में ही रहते हैं और बौद्ध अल्पसंख्यक हो गए हैं। भारत में मुसलमान आबादी में वे शामिल नहीं हैं, जो जनगणना जैसे अभियानों का बहिष्कार करते रहे हैं। 65 साल की मुस्लिम आबादी में रोहिंग्या भी शामिल नहीं हैं।

इस लिहाज से मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी अधिक हो सकती है। रपट के मुताबिक, हिंदुओं के साथ-साथ जैन और पारसी की आबादी भी घटी है। मुसलमानों के अलावा सिख, बौद्ध, ईसाई की आबादी बढ़ी है। जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध, सिख समुदाय भी अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। देश में पारसियों की आबादी तो करीब 57000 बताई जाती है, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों के लिए कभी भी जन-आंदोलन नहीं छेड़े। मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती रही है, इसके बुनियादी कारण बांग्लादेश से घुसपैठ, धर्मान्तरण, मुस्लिम सांसदों, नेताओं द्वारा ज्यादा बच्चे पैदा करने के आह्वान, 'पालन-पोषण तो अल्लाह करेंगे' जैसी सोच, 2011 तक ज्यादा प्रजनन दर, अशिक्षा, अज्ञानता आदि हैं। यह बढ़ोतरी देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती है। देश के संसाधन कम पड़ सकते हैं। पहले घुसपैठ बांग्लादेश से अधिक हुई, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान विभाजन के साथ युद्ध भी हुआ। लोग बांग्लादेश से भाग कर भारत में आए। संघ-भाजपा 2 करोड़ से अधिक ऐसे घुसपैठिए मानते रहे हैं। जब म्यांमार से पलायन शुरू हुआ, तो रोहिंग्या मुसलमानों ने भारत में घुसपैठ की। म्यांमार के बाद भारत में हिंदुओं की आबादी में सर्वाधिक गिरावट हुई है। रपट बताती है कि दुनिया में बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी 22 फीसदी घटी है। प्रजनन दर की बात बेहद महत्वपूर्ण है। दशकों तक मुसलमानों की औसत प्रजनन-दर 4-6 फीसदी रही, लेकिन अब 2021 वाले दौर में यह घटकर 2.36 फीसदी हो गई है।

## चर्चा

# चलते सिक्कों के नाम

उम्र की गलियों में जो तसदीक हो गए, वो चिनार अब पतझड़ के लिए ही हैं। राजनीति चलते सिक्कों का नाम है और यही राष्ट्र से प्रदेश तक के चुनावों में देखा जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हिमाचल में लोकसभा से विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस व भाजपा के उम्मीदवारों के चयन में प्रयास और कयास रहा। संगठन के कारण भाजपा ने अपने सिक्के जल्दी उछाले, जबकि कांग्रेस के लिए उपचुनावों में संगठन की तफतीश हो गई। यही वजह है कि भाजपा ने उपचुनावों में अपना सिक्का जमाने के लिए मूल कांग्रेसियों का भाजपा में अवतरण का महोत्सव बना डाला। बेशक यह दांव मुश्किल व चुनौती से भरा नजर आया, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के कुछ सिक्के छीन कर चुनावी आकाश में उछाल दिए। कम से कम कांग्रेस इन्हें खोटा नहीं कह सकी, भले ही इन्हें बागी कहे या इनके बीच सरगना खोजती रहे। कांग्रेस से छिटक कर भाजपा के उम्मीदवार बने नेताओं ने सियासत का मनोविज्ञान बदला है और इसका असर उनके भविष्य व पार्टियों के परिदृश्य को नए सिरे से पढ़ रहा है। टिकट आबंटन के चक्रब्यूह में भाजपा ने सियासत की शतरंज को भी हैरान किया है, लेकिन कल इसी बिसात पर चुनावी परिणाम की अपनी एक हैसियत होगी। उपचुनाव में एक भी सीट जीतने पर भाजपा की सफलता का परिणाम सोलह प्रतिशत का लाभ देगा। जाहिर है इस हानि का भागीदार वक्त कांग्रेस के लिए महंगा साबित हो सकता है।

इसलिए भाजपा के पास कांग्रेस के सिक्के हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी भाजपा के दो सिक्के आजमाते हुए डा. राम लाल मार्कंडेय को उछाल कर फेंक दिया। ऐसे में अनुराधा राणा का लाहुल-स्पीति से उम्मीदवार बनना नई करवटों का संगम है। सियासत के शिखर और सियासत के सिफर में अंतर केवल वक्त, विमर्श, वकालत और बगावत का है। हिमाचल में बागी या बगावत न होती, तो छह उपचुनाव या निर्दलयों के इस्तीफे अदालत में न होते। बहरहाल चुनावों की देहरी पर आकर राजनीतिक पार्टियों का व्यवहार असामान्य होने की वजह सत्ता की अंगुलियां चलाने जैसा हो जाता है। ऐसे में हर चुनाव को उम्मीदवारों की ताजगी चाहिए, लेकिन यह असंभव होता जा रहा है। जिस तरह चुनावी पांव से पाजेब लंबी होती जा रही है, उसी तरह कोई भी वरिष्ठ नेता अपनी विरासत नहीं छोडऩा चाहता। भाजपा ने मार्गदर्शक मंडल बना कर प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार सरीखे नेताओं के योगदान को पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार की काबिलीयत में चंद्र कुमार या धनी राम शांडिल की उम्र पर गौर नहीं करती। इसी संदर्भ में डा. राम लाल मार्कंडेय भी खुद को राजनीतिक उम्र में संभालने के लिए भाजपा से दूर, कांग्रेस से मजबूर होकर अब निर्दलीय होकर जौहर दिखाना चाहते हैं। क्या राजनीति लोकतंत्र के लिए चुनाव का व्यवहार ओढ़ती है या सत्ता के निष्कर्ष में खुद को संभालती है। जो भी हो, हिमाचल इस समय केवल दो राजनीतिक पार्टियों में ही नहीं बंटा, बल्कि जनता के उसूल, सत्ता के कबूल और उम्मीदवारों के रसूख पर भी मत विभाजन होगा। राजनीतिक शिथिलता अगर जनता को पसंद नहीं, तो सत्ता के संघर्ष में नेताओं के प्रदर्शन पर भी वोटों की मंडी बंटी हुई नजर आती है। कमोबेश इन चुनावों में हिमाचल दो सरकारों के बीच कहीं प्रधानमंत्री के आभामंडल से उम्मीद कर रहा है, तो कहीं मुख्यमंत्री की तस्वीर से खुद को नत्थी कर रहा।

सत्यपाल वशिष्ठा, स्वतंत्र लेखक

# नर्सिंग का पेशा दुनिया भर में भरोसेमंद

**गंभीर बात है कि निजी संस्थानों में नर्सिस को वेतन कम दिया जाता है तथा काम ज्यादा लिया जाता है'**

हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। बहुत से देशों में 6 मई से 12 मई तक नर्सिस सप्ताह मनाया जाता है। पूरे सप्ताह सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तरीय ज्ञान का आदान-प्रदान किया जाता है जो नर्सिस की कार्यशैली में गुणवत्ता लाने में सहायक होता है। हर वर्ष नए थीम के साथ यह दिवस मनाया जाता है जो नर्सिंग पेशे में गुणवत्ता लाने के लिए प्रेरित करता है। इसी कड़ी में वर्ष 2024 का थीम है 'हमारी नर्सें, हमारे भविष्य, रोगी देखभाल की आर्थिक शक्ति'। नर्सें लोगों की सेहत को बनाए रखने में नींव का पत्थर होते हुए अपने आप आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से हमेशा संघर्षशील हैं। इसलिए इस वर्ष के थीम में प्रमुखता से नर्सिंग पेशे/क्षेत्र में रणनीतिक निवेश के ऊपर जोर देता है। नर्स किसी भी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी। वे चिकित्सा प्रतिष्ठान में प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक अपने मरीजों की भलाई के लिए जिम्मेदार हैं। वे चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए डॉक्टरों के साथ सांझेदारी करती हैं। वे मरीजों के स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करती हैं। इस वजह से नर्सिंग का पेशा दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद पेशों में से एक पेशा बन गया है।

पहले इसे एक मामूली पेशे के रूप में देखा जाता था, परंतु फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को एक संगठित पेशा बनाया। 1860 में पहला आधिकारिक नर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाकर और नर्सों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में चिकित्सा और देखभाल के आधुनिक विचारों को एकीकृत करके नर्सिंग पेशे की स्थिति को ऊंचा उठाने में मदद की। नाइटिंगेल ने देखभाल के मानक स्थापित किए। पूरे विश्व में नर्सिंग क्षेत्र में क्या नए विकास/अनुसंधान हुए, उन सबके अवलोकन के लिए 1965 में दुनिया भर में 20 मिलियन से अधिक नर्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले 130 से अधिक राष्ट्रीय नर्सिस संघों का एक संघ, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ने 12 मई को पहली बार फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर नर्सों का जश्न मनाया। 1974 में आधिकारिक तौर पर इसे अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस नाम दिया गया था। इस दिवस का उद्देश्य एक स्वस्थ और फिट समाज को बनाए रखने में नर्सिस की कड़ी मेहनत को पहचानना और उसका जश्न मनाना है। नर्सिंग स्टाफ के कई कार्यस्थल मुद्दों और चिंताओं पर ध्यान आकर्षित करने में मदद करता है। यह एक व्यवहार्य और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण करियर के रूप में नर्सिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। क्योंकि एक अनुमान के अनुसार 2030 तक सारे संसार में 18 मिलियन स्वास्थ्य कर्मचारी कम होंगे, इसके लिए अधिक भर्ती, प्रशिक्षण आदि के लिए ठोस कार्रवाई पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में नर्सिंग स्टाफ के महत्व का असली पता हमें कोविड-19 और कोविड-20 में लगा, जब नर्सिस ने अपने आप को अग्रिम पंक्ति की कार्यकर्ता बनकर खुद को आग से खेलने के लिए तैयार किया। अपने परिवार को दूर रखा, परिवार के डर को कम करने के लिए जानबूझकर जानकारी छिपाई। पीपीई किट के साथ 12-12 घंटे मौत के साये में काम किया। महामारी की पहली लहर के दौरान आईसीएन ने दुनिया भर में नर्सिस के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों में 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। यह अपर्याप्त जनशक्ति के कारण नर्सिस को अधिक काम के दबाव के कारण हुआ। सारे विश्व में नर्सिस की 10 मिलियन तक की कमी है। 2018

में एक अध्ययन के अनुसार जिन रोगियों को गहन देखभाल की आवश्यकता होती है, वे अपना 86 प्रतिशत से 88 प्रतिशत समय नर्स के साथ बिताते हैं। नर्सिंग एक विविध क्षेत्र है।

अजन्मे बच्चे की देखभाल से लेकर जीवन के अंत तक देखभाल करने तक नर्सें प्रतिदिन जीवन और मृत्यु के मामलों को निपटाने के लिए उच्च तनाव वाले वातावरण में काम करती हैं। 2006 में मेडसर्ग नर्सिंग द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि एक नर्स एक औसत शिफ्ट के दौरान 8 किलोमीटर चलती है। नर्सें कई रोगियों की देखभाल की पहली पंक्ति होती हैं, इसलिए उन्हें अक्सर रोगियों या उनके परिवारों की ओर से हिंसा का शिकार भी होना पड़ता है। नर्सें अपना जीवन दाव पर लगाकर उन लोगों की देखभाल करती हैं जो संक्रामक रोगों के कारण बीमार होते हैं। भारत में 35.14 लाख रजिस्टर्ड नर्सिस हैं, जिसका अनुपात 2.06 नर्सिस प्रति 1000 व्यक्ति बनता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक, जो 3 नर्सिस प्रति हजार व्यक्ति है, से काफी नीचे है। भारतवर्ष में इस अनुपात के कम होने का कारण यह भी है कि अच्छे वेतन के लिए भारत से नर्सिस का पलायन दूसरे देशों को हो रहा है। सरकार को इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में यह अनुपात और निचले स्तर पर है। 9 जून 2023 के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग में सिस्टर ट्यूटर के 29 पद, वार्ड सिस्टर और नर्सिंग सिस्टर के 27 पद, स्टाफ नर्स के 647 पद, मेल हेल्थ वर्कर के 1846 और फीमेल हेल्थ वर्कर के 1091 पद खाली हैं। हिमाचल की जनसंख्या इस समय 6864602 है। हिमाचल की जनसंख्या बढ़ रही है, उसके अनुरूप स्वीकृत पदों को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर इलाके ग्रामीण एवं दुर्गम हैं। यहां नर्सिस ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। नर्सिस के कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए तथा कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता है। इसके लिए हर महीने खंड स्तर, तहसील स्तर और जिला स्तर तथा अन्य संस्थानों के स्तर पर नर्सिस के साथ सभा हो तथा इनकी मांगों का मौके पर ही निपटारा हो।

नर्सिस को कार्य शिफ्टों में करना पड़ता है। इनकी सुविधा के लिए आवास अस्पताल या डिस्पेंसरी के परिसर में ही हो ताकि वे अपने बच्चों तथा बुजुर्गों को अपनी ड्यूटी के साथ-साथ देख सकें। नर्सिस की कोई भी भर्ती आउटसोर्सिंग पर नहीं होनी चाहिए। निजी स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सिस को वेतन कम दिया जाता है तथा काम ज्यादा लिया जाता है। इसके लिए सरकार को अधिनियम बनाकर इनको सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि नर्सिस को आर्थिक शोषण से बचाया जा सके। नर्सिस के लिए समय-समय पर योग सत्र लगाने चाहिएं ताकि उनको काम के बोझ से जो मानसिक तनाव है, उससे राहत दिलाई जा सके।

# छिलकों की छाबड़ी : भितरघाती तैयार बैठे हैं'

मामला बड़ा रोचक हो गया है। मामला राजनीतिक है और राजनीति बड़े गुल खिलाती है। गुल गुलशन गुलफाम बना देती है। पब्लिक देख रही है कि चुनावी तमाशे में एक दल का नेता दूसरे दल में है और दूसरे दल का नेता पहले दल में है और फिर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में डुगडुगी बजा रहे हैं। कोई भी दल दूसरे दल से आए नेताजी को दिल से स्वीकार नहीं कर रहा। लेकिन हाईकमान का डंडा है कि ऊपर ऊपर से स्वीकार करना पड़ रहा है और भीतर भीतर से भितरघात का खेल खेलने की तैयारी हो रही है। दुश्मन दुश्मन इक्_ हो गए हैं। नैतिकता का चीरहरण हो गया है। वर्कर कंफ्यूज हो गया है। सेटिंग का ऐसा दौर चला है कि राजनीति के चाणक्य भी शरमा रहे हैं। एक नेता जो सुबह मंच पर आकर अपने दल द्वारा उतारे गए प्रत्याशी के समर्थन में भाषण दे रहा है तो रात को वही नेता व्हाट्सएप कॉल करके अपने समर्थकों को कह रहा है कि इसको आपका वोट नहीं जाना चाहिए। पार्टी का आदेश जाए भाड़ में, लेकिन गुपचुप तरीके से पार्टी द्वारा उतारा गया प्रत्याशी भाड़ में झोंकने के लिए कमर कस लेनी है। ऐसा नेता अपने समर्थकों को समझाता है कि उसूल वसूल कुछ नहीं होते। राजनीतिक उसूलों से ऊपर होती है। इसलिए ऊपर ऊपर प्रत्याशी के साथ दिखना चाहिए और भीतर भीतर उसे रगड़ा देना चाहिए। यह नई चाणक्य नीति है। पुरानी चाणक्य नीति अब पुरानी हो गई है क्योंकि अब नई सदी की राजनीति है। इसमें प्रलोभन दिए जाते हैं। गारंटियां दी जाती हैं। सब्जबाग दिखाए जाते हैं और फिर सरकार बनने पर पीठ दिखाई जाती है। जनता से नजरें चुराई जाती हैं। नई तरह की इस राजनीति में दो ध्रुव विरोधी दलों के बड़े नेता रात को व्हाट्सएप कॉल करके एक दूसरे को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि अधिकृत प्रत्याशी के साथ-साथ चल रहे उनकी पार्टी के भितरघाती गुल खिलाने के लिए तैयार बैठे हैं।

ऐसा कहते हुए दोनों मुस्कुराते हैं। ठहाके लगाते हैं। एक दूसरे को अग्रिम बधाई देते हैं। लोकतंत्र की आत्मा बाग-बाग हो जाती है। नेताजी की तबीयत हरी हरी हो जाती है। भितरघाती दोनों तरफ से पैसा लेते हैं। उनकी तबीयत बाग-बाग हो जाती है। अब इलेक्शन का माहौल है। भितरघाती दोनों तरफ घात लगाकर बैठे हैं। हाईकमान धृतराष्ट्र बना बैठा है। पब्लिक कंफ्यूज है। नेता लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र महफूज है। उनके होते लोकतंत्र का हाजमा खराब नहीं हो सकता। पेट में गड़बड़ नहीं हो सकती। लोकतंत्र को गैस्टिक की समस्या नहीं हो सकती। लोकतंत्र को जुकाम नहीं हो सकता। खांसी नहीं हो सकती। जब तक भितरघाती बैठे हैं, तब तक लोकतंत्र की सेहत को डायरेक्ट तौर पर कोई खतरा नहीं है। पब्लिक भितरघातियों को पहचानती है। वह उनकी अदाओं पर बलिहारी है। पब्लिक का मानना है कि यही भितरघाती लोकतंत्र की सवारी हैं। इनके रहते लोकतंत्र की जड़ों को कोई ताकत खोखला नहीं कर सकती। भितरघाती सम्मान के पात्र हैं। अगर चुनावों में भितरघाती मौजूद न हों तो फिर चुनाव का मजा नहीं रह जाता। ऐसे लोग अपनी-अपनी पार्टियों की आन, बान व शान होते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से चुनाव दिलचस्प हो गए हैं। चुनाव दिलचस्प हो जाएं तो लोग दिलचस्पी लेते हैं। अब पब्लिक की दिलचस्पी बढ़ गई है। भितरघातियों की कीमत बढ़ गई है। वे बेशकीमती हो गए हैं। भितरघाती किसी के बीच समीकरण बिगाड़ सकते हैं। नाकों चने चबवा सकते हैं। उनकी ताकत के आगे लोकतंत्र बलिहारी है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए भितरघाती तैयार बैठे हैं। बस उन्हें एक अदद आदेश का इंतजार है। आदेश कई बार इशारों इशारों में भी आता है। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो! यह बड़े राज का मामला है भाई।

# यूपीआई से बढ़ रही फिजूलखर्ची की लत? जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

**यूनिफाइड पेमेंट्स सिस्टम (UPI) ने भारत में डिजिटल पेमेंट का कायाकल्प कर दिया। आज शॉपिंग मॉल से लेकर सब्जी की दुकान पर यूपीआई पेमेंट की सुविधा मिल जाएगी। लोग रोजमर्रा का सामान तो यूपीआई के जरिए खरीद ही रहे वे महंगे होम अप्लायंसेज महंगे गैजेट और डिजाइन कपड़ों के बिल का भुगतान भी इसी से कर रहे हैं। लेकिन इससे फिजूलखर्ची बढ़ने की बात भी कही जा रही है।**

**नई दिल्ली।** यूनिफाइड पेमेंट्स सिस्टम (UPI) ने भारत में डिजिटल पेमेंट का कायाकल्प कर दिया। आज आपको बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल से लेकर पान और सब्जी की दुकान पर यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिल जाएगी। लोग रोजमर्रा का सामान तो यूपीआई के जरिए खरीद ही रहे, वे महंगे होम अप्लायंसेज, महंगे गैजेट और डिजाइन कपड़ों के बिल का भुगतान भी इसी से कर रहे हैं।

भारत के पेमेंट सिस्टम को डिजिटल करने और नकदी का चलन कम करने के सफर में इसकी भूमिका काफी अहम है। लेकिन, इस सहूलियत का एक नकारात्मक पक्ष भी है। समाचार एजेंसी आईएएनएस ने एक्सपर्ट के हवाले से बताया कि यूपीआई से लोगों को फिजूलखर्ची की भी लत लग रही है। वे ऐसे भी सामान खरीद ले रहे हैं, जिनकी असल में उस वक्त उन्हें जरूरत नहीं होती।

**यूपीआई से क्यों बढ़ रही फिजूलखर्ची?**

UPI/QR कोड के माध्यम से खरीदारी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह हैं स्मार्टफोन। आज देश की बड़ी आबादी के पास स्मार्टफोन और डेटा की पहुंच हो गई है। वे स्मार्टफोन के जरिए किसी भी चीज का पेमेंट चुटकियों में कर देते हैं। यही फिजूलखर्ची की वजह भी बन रहा है।

IIT दिल्ली का एक हालिया सर्वे बताता है कि यूपीआई और अन्य डिजिटल पेमेंट ऑप्शन की वजह से करीब 74 फीसदी लोग 'जरूरत से ज्यादा खर्च' कर रहे हैं। दरअसल, नकद पैसों की तुलना में डिजिटल मोड से पेमेंट करना काफी आसान है। नकदी में कभी चेंज जैसी समस्या हो जाती है, या फिर उस वक्त आपके पास उतने पैसे नहीं होते, तो आप खरीदारी से रुक जाते हैं।

लेकिन, यूपीआई या किसी दूसरे डिजिटल पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती। आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे होते हैं, समझ लीजिए कि वे आपके स्मार्टफोन में हैं। यहां तक कि आप क्रेडिट कार्ड जैसे माध्यमों के इस्तेमाल से बैंक अकाउंट से ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं। आप दोस्तों या रिश्तेदारों से फौरन उधार भी ले सकते हैं।

**क्या कह रहे हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट?**

मार्केट इंटेलिजेंस फर्म सीएमआर में इंडस्ट्री इंटेलिजेंस ग्रुप के हेड प्रभु राम ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया, 'इस तरह की सहूलियत से फिजूलखर्ची बढ़ने की काफी संभावना रहती है, क्योंकि यह डिजिटल मोड रहता है। इसमें हाथ से नकद पैसे देने की तरह नहीं लगता कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं।'

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के लेटेस्ट डेटा से पता चला है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन की संख्या अप्रैल में 1,330 करोड़ तक पहुंच गई। इसमें सालाना आधार पर 50 फीसदी का इजाफा हुआ है। पिछले साल यूपीआई लेनदेन लगभग 60 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड 11,768 करोड़ तक पहुंच गया था।

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में उपभोक्ता खर्च बढ़ रहा है। अब लोग कार, स्मार्टफोन, टीवी और अन्य वस्तुओं पर जमकर पैसा खर्च कर रहे हैं। इससे देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि, यह भी देखा जा रहा है कि यूपीआई की वजह से लोग कुछ ऊंचे दाम वाली वस्तुओं पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और यह चलन लगातार बढ़ रहा है।

# 10 वर्षों में 138 अरब डॉलर होगा डिफेंस सेक्टर, क्या शेयरों में बनेंगे कमाई के मौके?

**अगले 10 वर्षों के दौरान भारत के रक्षा क्षेत्र बाजार का आकार 138 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है। रेटिंग एजेंसी नोमुरा का कहना है कि रक्षा उपकरणों प्रौद्योगिकियों और सेवाओं की बढ़ती मांग से इस क्षेत्र के बाजार को बढ़ने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ समय में डिफेंस सेक्टर के शेयरों ने जोरदार रिटर्न दिया है। आइए जानते हैं कि क्या अभी भी उनमें कमाई का मौका है।**

डिफेंस सेक्टर की प्रमुख कंपनियों का पिछले 6 महीने का रिटर्न

| डिफेंस कंपनी | शेयर प्राइस | 6 महीने में रिटर्न |
|---|---|---|
| हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड | 3,877.00 रुपये | 88.17% |
| डेटा पैटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड | 2,812.00 रुपये | 50.50% |
| सिका इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड | 1,985.40 रुपये | 58.00% |
| भारत डायनामिक्स लिमिटेड | 1,868.00 रुपये | 72.52% |
| हाई एनर्जी बैटरीज (इंडिया) लिमिटेड | 784.95 रुपये | 38.17% |
| तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड | 440.00 रुपये | 76.25% |

परिवहन विशेष न्यूज

**नई दिल्ली।** अगले 10 वर्षों के दौरान भारत के रक्षा क्षेत्र बाजार का आकार 138 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है। रेटिंग एजेंसी नोमुरा ने अपनी 'इंडिया डिफेंस' रिपोर्ट में कहा है कि रक्षा उपकरणों, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं की बढ़ती मांग से इस क्षेत्र के बाजार को बढ़ने में मदद मिलेगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2029-30 तक रक्षा पर पूंजीगत व्यय बढ़कर इस क्षेत्र के कुल बजट का 37 प्रतिशत पर पहुंच सकता है, जिसके चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 29 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 से 2029-30 के दौरान इस क्षेत्र में 15.5 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है जिसमें पिछले अवधि के मुकाबले महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

नोमुरा की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार अनुकूल नीतिगत सुधारों, स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और तकनीकी विकास जैसे उपायों से रक्षा क्षेत्र का समर्थन कर रही है।

**डिफेंस सेक्टर के शेयरों में जोरदार तेजी**

डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के शेयर पिछले कुछ समय से काफी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से लगभग सभी कंपनियों ने पिछले 6 महीने में 50 फीसदी या इससे अधिक का रिटर्न दिया है। डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने तो सबसे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसने पिछले 6 महीने में 88.17 फीसदी और 1 साल में 160.73 फीसदी का बंपर रिटर्न दिया है।

# शहरों में सुस्त रहेगा घरेलू खर्च, ग्रामीण इलाकों में पानी की तरह बहेगा पैसा; जानिए क्या है पूरा मामला

परिवहन विशेष न्यूज

**वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत के ओवरऑल घरेलू खर्च (Household Spending) में सुस्ती का अनुमान है। गुड्स और सर्विसेज पर घरेलू खर्च में ग्रोथ काफी कम रहेगी। इसमें पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 4-5 फीसदी का उछाल दिख सकता है। साल 2011 से 2020 के दौरान इसमें 6.5-7 फीसदी का तेज उछाल दिखा था। हालांकि रूरल और लग्जरी खर्च में सुधार होने की उम्मीद है।**

**नई दिल्ली।** भारत का घरेलू खर्च (Household Spending) वित्त वर्ष 2024-25 में सुस्त बनी रहने का अनुमान है। हालांकि, रूरल और लग्जरी खर्च में सुधार होने की उम्मीद है। यह बात स्विटजरलैंड की फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली UBS की रिपोर्ट 'इंडिया इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स' में कही गई है।

**क्या कहती है UBS की रिपोर्ट?**

UBS की रिपोर्ट का अनुमान है कि गुड्स और सर्विसेज पर घरेलू खर्च में ग्रोथ काफी कम रहेगी। इसमें पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 4-5 फीसदी का उछाल दिख सकता है। साल 2011 से 2020 के दौरान इसमें 6.5-7 फीसदी का तेज उछाल दिखा। उसकी तुलना में यह ग्रोथ काफी सुस्त मानी जा रही है।

**क्यों नहीं ज्यादा बढ़ेगा घरेलू खर्च?**

रिपोर्ट कुछ अहम वजहें भी बताती है, जिसके चलते घरेलू खर्च में मजबूत उछाल आने के आसार नहीं हैं। एक कारण यह है कि अब शहरों में रहने वाले लोग पहले की तरह खर्च नहीं करते, क्योंकि कंपनियां पहले की तरह वेतन नहीं बढ़ा रहीं। साथ ही, लोग अब घर को छोड़कर दूसरी चीजें खरीदने के लिए कर्ज भी ज्यादा नहीं ले रहे। UBS की रिपोर्ट का यह भी कहना है कि अब बैंक कर्ज देने के मामले में ज्यादा सतर्क हो गए हैं।

**लेकिन यहां पानी की तरह बहेगा पैसा**

ओवरऑल खर्च में भले ही बड़ा इजाफा ना हो, लेकिन समाज के कुछ हिस्से महंगी चीजों की खरीदारी जारी रखेंगे। UBS की रिपोर्ट के मुताबिक, रईस लोग पहले की पैसे उड़ाना जारी रख सकते हैं। वहीं, ग्रामीण इलाकों में भी घरेलू खर्च में कुछ तेजी आ सकती है।

पिछले दिनों मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि इस साल मानसून सामान्य से अच्छा रहेगा। अगर अच्छे मानसून से कृषि उपज बढ़ती है, तो ग्रामीण इलाकों में डिमांड में तेजी आ सकती है। अगर सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात की इजाजत देती है, तो भी रूरल डिमांड बढ़ेगी।

# कर्ज चुकाने के पैसे नहीं, क्या दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान? IMF ने जताई ये चिंता

परिवहन विशेष न्यूज

**अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान की कर्ज चुकाने की क्षमता पर गंभीर संदेह जताया है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान भारी नकदी संकट से जूझ रहा है और उसे लोन रीपेमेंट में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। IMF की सपोर्ट टीम पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद पहुंची है। पाकिस्तान एक बार फिर बेलआउट पैकेज मांग रहा है।**

**नई दिल्ली।** संयुक्त राष्ट्र की फाइनेंशियल एजेंसी-अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान की कर्ज चुकाने की क्षमता पर गंभीर संदेह जताया है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान भारी नकदी संकट से जूझ रहा है और उसे लोन रीपेमेंट में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

दरअसल, पाकिस्तान ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EPF) के तहत नए बेलआउट पैकेज की गुजारिश की थी। इसके बाद IMF की सपोर्ट टीम पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद पहुंची है। उसी ने पाकिस्तान के कर्ज चुकाने की क्षमता पर संदेह जताया है।

पाकिस्तान के जियो न्यूज ने पिछले दिनों पाकिस्तान पर अपनी स्टाफ रिपोर्ट जारी की थी। इसमें उसने IMF के हवाले से कहा, 'पाकिस्तान की फंड चुकाने क्षमता काफी कमजोर है। इसमें कई जोखिम भी हैं। पाकिस्तान जरूरी नीतियों पर अमल करने तक के लिए भी बाहरी मदद पर बुरी तरह से निर्भर है।'

रिपोर्ट के मुताबिक, 'पाकिस्तान आर्थिक सुधारों को अपनाने में देरी कर रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी कम हो गया है। कैश फ्लो भी बड़ी गिरावट आई है। सामाजिक और सियासी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। इन सबके चलते नीतियां लागू करने में भी दिक्कत हो रही है। उसका लोन रीपेमेंट कैपिसिटी और क्रेडिट स्टेबिलिटी भी खत्म हो गई है।'

**पाकिस्तान को भारी कर्ज की जरूरत**

ग्लोबल लेंडर IMF का कहना है कि पाकिस्तान को अगले पांच साल के दौरान 123 अरब डॉलर की फंडिंग की जरूरत होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि IMF की सपोर्ट टीम पाकिस्तान के वित्तीय दल के साथ अगले लॉन्ग टर्म लोन प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेगी।

वहीं, आगे का फैसला IMF मिशन लेगा, जो 16 मई को पाकिस्तान आएगा। वह अलग-अलग विभागों से डेटा लेगा और मौजूदा वित्त वर्ष के बजट के बारे में भी चर्चा करेगा। IMF की टीम 10 दिनों तक पाकिस्तान में रहेगी। पाकिस्तान ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत तीन साल के लिए 6 और 8 अरब डॉलर के अगले बेलआउट पैकेज की मांग की है।

हालांकि, IMF पहले ही साफ कर चुका है कि पाकिस्तान को आर्थिक सुधारों में तेजी लानी होगी। इसमें अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ विदेशी कर्ज घटाने का उपाय करने जैसी चीजें शामिल हैं।

**चीन, सऊदी भी कर्ज ले रहा पाक**

इस बीच पाकिस्तान बाहरी वित्तपोषण में 23 अरब डॉलर के भारी अंतर को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में चीन जैसे प्रमुख सहयोगियों से करीब 12 अरब डॉलर का कर्ज लेने वाला है। पाकिस्तान सरकार असल में IMF मिशन टीम के आने से पहले बजट टारगेट को हासिल करना चाहती है।

पीटीआई ने वित्त मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर, संयुक्त अरब अमीरात से 3 अरब डॉलर और चीन से 4 अरब डॉलर की मदद लेगा। वहीं, पाकिस्तान को नए लोन प्रोग्राम के तहत IMF से 1 अरब डॉलर से अधिक की मदद मिलेगी।

पाकिस्तान ने अनुमानित बजट में वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी नई फंडिंग को शामिल किया है। पाकिस्तान वित्तीय संस्थानों के साथ नए लोन प्रोग्राम के समझौते करेगा। पाकिस्तान का बजट जून में आ सकता है। वहीं, IMF के साथ नए लोन प्रोग्राम की बात मई के मध्य में शुरू होने की उम्मीद है।

**दिवालिया होने वाला था पाक**

पाकिस्तान पिछली गर्मियों में डिफॉल्ट होने से बाल-बाल बचा था। दरअसल, IMF की शर्तें मानने में पाकिस्तान आनाकानी कर रहा था। ऐसे में IMF भी कर्ज देने को राजी नहीं हो रहा था। हालांकि, IMF ने ऐन मौके पर बेलआउट पैकेज को मंजूर करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया।

अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार जरूर आया है। मुद्रीस्फीति पिछले साल मई में 38 प्रतिशत के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं, इस साल अप्रैल में यह घटकर 17 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। इससे आम जनता को महंगाई से कुछ राहत मिली है।

**क्या होता है बेलआउट पैकेज?**

बेलआउट पैकेज दरअसल किसी देश या फिर कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए दी जाने वाली वित्तीय मदद है। यह कर्ज, नकद, बॉन्ड या फिर स्टॉक खरीद के रूप हो सकती है। कई बार बेलआउट पैकेज को वापस लौटाने की शर्त भी होती है और कई बार नहीं भी होती। लेकिन, इसका समय-समय पर निरीक्षण और निगरानी की जाती है।

बेलआउट पैकेज का मकसद किसी ऐसे देश या बिजनेस को सपोर्ट देना होता है, जिसका देश या विदेश स्तर पर व्यापक असर पड़ सकता है। लाखों लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित हो सकती है।

अब जैसे पाकिस्तान की बात करें, तो उसके दिवालिया होने से करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। पाकिस्तान परमाणु क्षमता से लैस मुल्क भी है। उसके दिवालिया होने की सूरत में यह घातक हथियार गलत हाथों में भी पड़ सकता है, जिसका अंजाम काफी खतरनाक हो सकता है।

यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं लगातार बेलआउट पैकेज देकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने की कोशिश में लगी हैं।

# सामंजस्यपूर्ण शिक्षा: रिदमशाला छात्रों को संगीत से समृद्ध करती है

छात्रों के बीच समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए, डॉ. अंकुर शरण ने डीएवी स्कूल फ़रीदाबाद के साथ मिलकर एक प्रसिद्ध तालवादक और ड्रमर अंकुर द्वारा रिदमशाला, बीट बॉक्सिंग और ड्रमिंग कार्यशाला नामक एक अभिनव पहल शुरू की है। 200 से अधिक उत्साही प्रतिभागियों के साथ, रिदमशाला केवल संगीत के बारे में नहीं है; यह एक ऐसा मंच है जो लय की कला के माध्यम से अनुशासन, मर्यादा और एकता पैदा करता है। अंकुर लंबे समय से ऐसी रिदमशाला का आयोजन कर रहे हैं और हजारों छात्रों और स्वयंसेवकों के बीच बुनियादी शिक्षा देते हैं।

रिदमशाला का अंतर्निहित दर्शन संगीत शिक्षा से परे है। यह मानता है कि जब व्यक्ति लय में तालमेल बिठाते हैं, तो उनमें अनुशासन और सद्भाव की भावना पैदा होती है, जो संगीत के दायरे से परे जीवन के सभी पहलुओं तक फैली हुई है।

इसके मूल में, रिदमशाला का उद्देश्य छात्रों को लय के बुनियादी सिद्धांतों के साथ सशक्त बनाना है, जिससे वे इसकी बारीकियों की सराहना कर सकें और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में इसकी क्षमता का उपयोग कर सकें। इंटरैक्टिव सत्रों और आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से, छात्र न केवल संगीत वाद्ययंत्र बजाना सीखते हैं बल्कि सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में समन्वय और सहयोग के महत्व को भी समझते हैं।

हालाँकि, रिदमशाला संगीत शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। यह समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। स्वयंसेवकों की एक समर्पित टीम सड़क सुरक्षा से लेकर पर्यावरणीय स्थिरता तक विभिन्न पहलों का समर्थन करने के लिए अथक प्रयास करती है।

रिदमशाला के स्वयंसेवक सिर्फ सुविधाप्रदाता नहीं हैं; वे गुरु हैं जो छात्रों को जीवन के प्रति न्यूनतम दृष्टिकोण अपनाने और वर्तमान क्षण को संजोने के लिए प्रेरित करते हैं। वे छात्रों को स्कूल समुदाय के भीतर सहानुभूति और करुणा की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए प्रेम, सद्भाव और सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

रिदमशाला के माध्यम से, न केवल संगीतकारों की अगली पीढ़ी का पोषण किया जा रहा है, बल्कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिकों को भी तैयार किया जा रहा है, जो आत्मविश्वास और करुणा के साथ 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं।

जैसे-जैसे रिदमशाला का विकास जारी है, यह एक चमकदार उदाहरण के रूप में कार्य करता है कि कैसे शिक्षा पारंपरिक सीमाओं को पार कर सकती है और छात्रों को संगीत, प्रेम और सद्भाव से समृद्ध जीवन जीने के लिए सशक्त बना सकती है।

# पर्यावरण पाठशाला : गौरैया संरक्षण आखिर क्यों है ज़रूरी?

## *दाना-पानी रखें, लगायें घोंसला (बॉक्स) और पेड़, होगी गौरैया की घर वापसी -संजय कुमार*

"स्पैरो ( गौरैया )को **दिल्ली और बिहार का राज्य पक्षी घोषित किया गया है**। यहाँ एक प्रेरणादायक लेख है स्पैरो पर जिसे **संजय कुमार, पी.आई.बी, पटना के उपनिदेशक** ने लिखा है। इस लेख को **"गौरैया विशेष"** द्वारा **"परिवहन विशेष"** और **"ग्लोबल संघ गैर सरकारी संगठन"** के साथ संयुक्त आंदोलन के रूप में प्रकाशित किया गया है, हमारे राज्य पक्षी की संरक्षण के लिए।"

छोटे आकार वाली खूबसूरत गौरैया पक्षी का जिक्र आते ही बचपन की याद आ जाती है। कभी इसका बसेरा इंसानों के घर-आंगन में हुआ करता था। लेकिन पर्यावरण को ठेंगा दिखाते हुए कंक्रीट के जगंल में तब्दील होते शहर और फिर गांव ने इन्हें हमसे दूर कर दिया है। एक वक्त हुआ करता था जब हर घर-आँगन में सूप से अनाज फटका जाता था तो फटकने के बाद गिरे अनाज को खाने, गौरैया फुर्र से आती थी और दाना खा कर फुर्र से उड़ जाती थी। हम बचपन में इस पकड़ने की कोशिश करते हुए खेला करते थे। टोकरी के नीचे चावल रख इसे फंसाते और पकड़े के बाद गौरैया पर रंग डाल कर उड़ा देते। जब दूबारा वह आती थी, तो उसे पहचान कर मेरी गौरैया कह चहकते और खुश होकर ताली बचा कर उसका स्वागत करते थे।

अमूमन गौरैया हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, सिंड स्पैरो, रसेट स्पैरो, डेड सी स्पैरो और ट्री स्पैरो से जानी-पहचानी जाती है, लेकिन इनमें हाउस स्पैरो को घरेलू गौरैया कहा जाता है। यह गाँव और शहरों में पाई जाती हैं। इन्सान ने जहाँ भी घर बनाया देर सबेर गौरैया जोड़ा वहाँ रहने पहुँच ही जाती हैं। गौरैया छोटे पास्ता परिवार की पक्षी है। आंकडे बताते हैं कि विश्व भर में घर-आंगन में चहकने - फूदकने वाली छोटी सी प्यारी चिड़यि गौरैया की आबादी में कमी आई है।

**गौरैया इंसान का करती है अनुसरण**

वैज्ञानिक अध्ययनों की बात करें तो यह प्रमाणित हुआ है कि घरों में रहने वाली गौरैया सभी जगहों पर इंसान का अनुसरण करती हैं और जहां पर इंसान नहीं रहते हैं, वे वहां पर नहीं रह सकती हैं। बेथलहम की एक गुफा से 4,00,000 साल पुराने जीवाश्म के साक्ष्य से पता चलता है कि घरों में रहने वाले गौरैयों ने प्रारंभिक मनुष्यों के साथ अपना स्थान साझा किया था। रॉयल सोसायटी ऑफ लंदन की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंसानों और गौरैयों के बीच का बंधन 11,000 साल पुरानी बात है और घरेलू गौरैया के स्टार्च-फ्रेंडली होना हमें अपने विकास से जुड़ी कहानी को बताती हैं।

**गौरैया की संख्या में कमी के पीछे हैं कई कारण**

गौरैया की संख्या में कमी के पीछे कई कारण हैं जिन पर लगातार शोध हो रहे हैं। गौरैया की संख्या में कमी के पीछे के कारणों में बढ़ता आवासीय संकट, आहार की कमी, खेतों में कीटनाशक का व्यापक प्रयोग, जीवनशैली में बदलाव, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, शिकार, गौरैया को बीमारी और मोबाइल फोन टावर से निकलने वाले रेडिएशन को दोषी बताया जाता रहा हैं।

बढ़ता आवासीय संकट यानि एक पर्यावास का नुकसान है। गौरैया को घोंसला बनाने, खिलाने और बसेरा करने के लिए विशिष्ट प्रकार के आवासों की आवश्यकता होती है और इन आवासों को नष्ट किया जा रहा है। गौरैया के प्रजनन के लिए अनुकूल आवास में कमी भी इसकी संख्या में कमी का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। खपरैल/फूस के आवासों का तेजी से कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होने से तस्वीर बदल गयी है। शहरों में इनके प्रजनन के लिए अनुकूल आवास नहीं के बराबर है। यही वजह है कि एक ही शहर के कुछ इलाकों में ये दिखती है तो कुछ में नहीं। गौरैया संरक्षण में जुड़े लोग कृत्रिम घर बना कर गौरैया को प्रजनन के लिए आवास देने कि पहल चला रहे हैं। इसमें गौरैया अंडे देने के लिए आ भी रही है। कई गाँव में यह संकट ज्यादा नहीं है, फूस और मिट्टी के आवास अभी भी हैं। शहरीकरण, कृषि और औद्योगिक विकास सभी ने गौरैया के आवासों के नुकसान में योगदान दिया है। आहार की कमी / कीटनाशक का व्यापक प्रयोग प्रमुख कारक है जिसके कारण गौरैया की आबादी में गिरावट आई है। कीटनाशक सीधे तौर पर गौरैया को मार कर या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके खाद्य स्रोतों की उपलब्धता को कम करके प्रभावित कर सकते हैं। गौरैया अपने शिकार के माध्यम से कीटनाशकों के संपर्क में भी आती हैं, जो उनके शरीर में जमा हो सकते हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। गौरैया की आबादी में गिरावट में जलवायु परिवर्तन की भी भूमिका है। गौरैया तापमान और वर्षा में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती हैं, और उनके प्रजनन और प्रवास के पैटर्न को चरम मौसम की घटनाओं से बाधित किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से उनके खाद्य स्रोतों के वितरण, प्रचुरता, तापमान और वर्षा में परिवर्तन से उनकी आबादी में गिरावट आ सकती है।

एक वक्त हुआ करता था जब हर घर-आँगन में सूप से अनाज फटका जाता था, तो फटकने के बाद गिरे अनाज को खाने, गौरैया फुर्र से आती थी और दाना चुग कर फुर्र से उड़ जाती थी। हालांकि आज भी कई घरों में गौरैया आ रही है। कहीं इसका संरक्षण हो रहा है, तो कहीं नहीं। पैकेट बंद खाना, बाग़-बगीचा का नाश हो चुका है। पहले हर घर के आगे पीछे बाग़–बगीचा होता था। जहाँ झुरमुट वाला, नीबू, शमी अनार आदि का पेड़ होते थे जिस पर उनका आवास होता था। दिनों दिन बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण से गौरैया को नुकशान हो रहा है । गौरैया की आबादी में गिरावट का एक और कारण शिकार है। गौरैया का शिकार विभिन्न प्रकार के जानवर करते हैं, जिनमें शिकारी पक्षी, सांप और स्तनधारी शामिल हैं। वे घोंसले के शिकार के लिए भी असुरक्षित हैं, जो तब होता है जब उनके अंडे या चूजों को शिकारियों द्वारा ले लिया जाता है। कहीं कहीं पर बहेलिये शिकार कर रहे हैं। गौरैया के लिए एक और खतरा बीमारी भी है। गौरैया एवियन इन्फ्लूएंजा, वेस्ट नाइल वायरस और साल्मोनेलोसिस बीमारियों से प्रभावित हो सकती हैं।

**मोबाइल फोन टावर और गौरैया**

मोबाइल फोन टावर से निकलने वाले रेडिएशन को भी गौरैया के संख्या में कमी करने वाला एक बड़ा कारक माना जाता रहा है। लेकिन स्टेट ऑफ इंडियंस बर्ड्स 2020- रेंज, ट्रेंड्स और कंज़र्वेशन स्टेट्स ने अपने रिपोर्ट के पेज संख्या छह पर साफ-साफ कहा है कि गौरैया की संख्या में कमी के तथ्य में मोबाइल फोन टावर का जो तर्क दिया जाता रहा है उसे लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, जिससे यह पता चले कि रेडिएशन से गौरैया के प्रजनन पर प्रभाव पड़ता हो ? यानि यह भ्रम है कि मोबाइल फोन टावर से गौरैया के प्रजनन को खतरा होता है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि मोबाइल फोन टावर से निकलने वाले रेडिएशन प्रभाव डाल रहा है तो आप दूरसंचार मंत्रालय के वेबसाइट पर जाकर शिकायत किया जा सकता है।

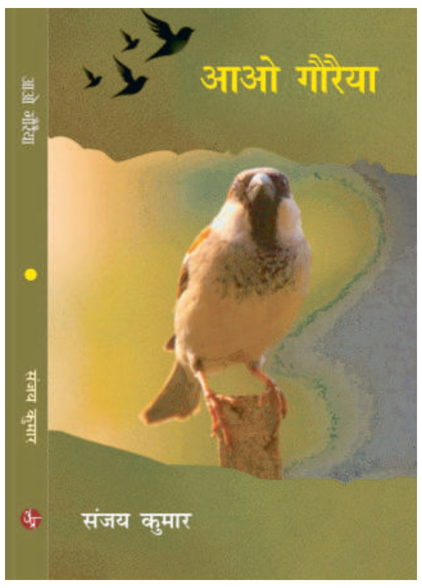


**25 साल से गौरैया की संख्या भारत में स्थिर बनी हुई**

हालांकि देश के छह मेट्रो बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में इनकी संख्या में कमी देखी गई है लेकिन बाकी के शहरों में इसकी संख्या स्थिर देखी जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता हैं कि भारत में यह विलुप्त नहीं है। लेकिन, स्थिति ठीक भी नहीं है। कई शहर और गाँव से गायब या पलायन कर चुकी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 25 साल से गौरैया की संख्या भारत में स्थिर बनी हुई है। हालाँकि, इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर दिल्ली सरकार ने 2012 और बिहार सरकार ने 2013 गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित कर रखा है।

संरक्षण का सवाल हर वर्ष 20 मार्च को 'विश्व गौरैया दिवस' के दिन सामने आता हैं। गौरैया इन्सानों की दोस्त है तो किसानों की मददगार है। गौरैया इंसान के साथ रहते हुये उन्हें सुख–शांति प्रदान करती हैं। खेत-खलिहान-फल-फूल–सब्जी में लगने वाले कीड़े–मकोड़ों से फसलों की ये रक्षा करती है। लेकिन, हमने ही इसे अपने से दूर कर दिया है। हालात यह है कि यह कहीं दिखती है, कहीं नहीं। एक शहर में है, दूसरे में नहीं। एक गाँव में है, दूसरे में नहीं। एक मुहल्ले में है दूसरे में नहीं हैं। ऐसे में गौरैया कहती है अभी मैं जिन्दा, अस्तित्व खतरे में है, करो पहल मुझे बचाने की, है वायदा घर-आँगन में चहचाहट से भर दूंगी खुशियाँ।

इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर(IUCN) ने 2002 में इसे लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल कर दिया था। गौरैया, गिद्ध के बाद सबसे संकट ग्रस्त पक्षी में से है। बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़े प्रसिद्ध पर्यावरणविद मोहम्मद ई दिलावर ने 2008 से गौरैया संरक्षण शुरु की थी। आज यह दुनिया कई देशों तक पहुंच गयी है। वैसे गौरैया से विश्व को प्रथम परिचय 1851 में अमेरिका के ब्रूकलिन इंस्टीट्यूट ने कराया था।

कुछ लोग घरों में दाना-पानी इसलिये नहीं रखते कि जब ये आती है तो इसके साथ कबूतर आदि चिड़यि भी आने लगती हैं और वे गंदा फैला देती हैं। कई लोग गिले कपड़े को सूखने डालते हैं तो चिड़यि कपड़ों पर बैठ जाती है और गन्दा कर देती हैं। देखा जाए तो लोगों के जीवन में काफी बदलाव भी आया है। बहुमंजली इमारत हो या आम भवन, खुले हिस्से या बालकोनी को लोग शीशे से पैक करवा देते हैं। यह खतरनाक होता है, गौरैया उड़ते हुये आती है और शीशे से टकरा जाती है या फिर उसमें अपनी परछाई देख उस पर चोंच मारती है उसे लगता है वहाँ दूसरी गौरैया है और ऐसे में वह घायल हो जाती है ।

गौरैया कई पारिस्थितिक तंत्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और बीजों के फैलाव और कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गौरैया संरक्षण का अलख राजकीय पक्षी घोषित राज्य दिल्ली और बिहार सहित पूरे भारत में जोर-शोर से चल रहा है। यही वजह है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गौरैया को देखा जा सकता है। पिछले कई सालों से गौरैया संरक्षण में लगे लोग, सरकारी-गैर सरकारी संस्थान, एनजीओ सहित हर आम और खास लोग, गौरैया फ़ोटो प्रदर्शनी, पेंटिंग प्रतियोगिता, दाना घर, घोंसला, पानी का बर्तन वितरण के साथ साथ जागरूकता अभियान से गौरैया की घर वापसी कराई हैं। देशव्यापी जागरूकता से गौरैया की घर वापसी होती दिख रही है। लोगों ने यह पहल दाना-पानी रखने, घोंसला ( बॉक्स ) लगाने और नन्ही सी जान गौरैया को थोड़ा सा प्यार देकर पूरा किया है। गौरैया ने भी वायदा निभाया है और लोगों के घर-आंगन, बालकनी, छत पर आकर अपनी चहचाहट से अपनी वापसी का अहसास करा दिया है।

गौरैया संरक्षण का अलख जागने से फायदा यह हुआ कि दूसरी चिड़यों का भी संरक्षण होने लगा। दाना पानी रखने और बॉक्स लगाने से दूसरी चिड़यि भी आने - दिखने लगी। बहरहाल, जब तक लोग इस मुहिम से नहीं जुड़ेंगे तब तक पक्षियों को लाभ पहुंचाना संभव नहीं हो पाएगा। यकीन मानिए जब आप अपने बर्तन से उनको पानी पीते हुए और आपके लगाये पेड़ - बॉक्स पर चिड़यि आएगी तो उसे देखेंगे और फिर आपको बहुत आत्मिक शांति मिलेगी। तो आइये, ओ री गौरैया को बचाएं रखे दाना-पानी, लगायें घोंसला ( बॉक्स ) और पेड़।

"यदि आप पर्यावरण पाठशाला का हिस्सा बनना चाहते हैं और गौरैया बचाओ मिशन #SaveSparrowMission का समर्थन करना चाहते हैं, तो अपनी कहानी Indiangreenbuddy@gmail.com पर साझा करें, जो MeraGhosla.com और ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ के सह संस्थापक और प्रबंधन ट्रस्टी डॉ. अंकुर शरण की एक पहल है।"

# स्वयंसेवीशाला : एक प्रभावी स्वयंसेवक बनने के लिए स्वयं को तैयार करना: सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए एक मार्गदर्शिका

स्वयंसेवा एक नेक प्रयास है जो आपके जीवन और दूसरों के जीवन को समृद्ध बना सकता है। चाहे आप पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय, या सामुदायिक विकास के प्रति उत्साही हों, एक अच्छा स्वयंसेवक बनने के लिए केवल दिखावा करने से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। यह तैयारी, समर्पण और बदलाव लाने के लिए सच्ची प्रतिबद्धता की मांग करता है।

हम विश्वगुरु बन रहे हैं, भारत युवा और ऊर्जावान है। हमारे युवाओं को वह सब कुछ मिल रहा है जो वे चाहते हैं, लेकिन अंततः यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसके प्रति कितना जुनूनी हैं और एक सोशलप्रिन्योर होने के नाते मार्गदर्शन करना मेरा नैतिक कर्तव्य है क्योंकि हमने एक स्वयंसेवक होने के नाते बहुत कुछ सीखा है। तो यहां कुछ सुनहरे नियम हैं जो मैंने अपने पारिस्थितिकी तंत्र से, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से काम करते समय और उनकी बारीकी से निगरानी करते हुए सीखे हैं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रारूप में सामाजिक कल्याण के लिए कुछ समय अवश्य देना चाहिए। एक मूल्यवान स्वयंसेवक बनने के लिए खुद को तैयार करने में आपकी मदद के लिए यहां कुछ आवश्यक कदम दिए गए हैं:

**अपने जुनून और कौशल को पहचानें:** अपनी रुचियों, मूल्यों और कौशल पर विचार करके शुरुआत करें। आप किस कारण से उत्साहित हैं? आपके पास कौन सी प्रतिभाएं या योग्यताएं हैं जो स्वयंसेवक की भूमिका के लिए फायदेमंद हो सकती हैं? इन कारकों की पहचान करने से आपको स्वयंसेवी अवसर खोजने में मदद मिलेगी जो आपकी ताकत और जुनून के अनुरूप हों।

**स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें:** स्वयंसेवा शुरू करने से पहले, आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कुछ समय लें। आप क्या प्रभाव डालना चाहते हैं? चाहे यह एक निश्चित संख्या में लोगों की मदद करना हो, नए कौशल सीखना हो, या किसी विशिष्ट परियोजना में योगदान देना हो, लक्ष्य रखने से आप अपने पूरे स्वयंसेवक अनुभव के दौरान केंद्रित और प्रेरित रहेंगे।

**शोध स्वयंसेवी अवसर:** एक बार जब आपको अपनी रुचियों और कौशलों की स्पष्ट समझ हो जाए, तो अपने समुदाय में या ऑनलाइन स्वयंसेवी अवसरों पर शोध करें। समय की प्रतिबद्धता, स्थान और संगठन या कारण की विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे कारकों पर विचार करें।

**अभिविन्यास और प्रशिक्षण सत्र में भाग लें:** कई स्वयंसेवी संगठन स्वयंसेवकों को उनके मिशन, नीतियों और प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण सत्र प्रदान करते हैं। संगठन के लक्ष्यों, जिस समुदाय की वह सेवा करता है, और एक स्वयंसेवक के रूप में अपनी भूमिका के बारे में अधिक जानने के लिए इन अवसरों का लाभ उठाएं। प्रशिक्षण सत्र आपके स्वयंसेवी कार्य से संबंधित मूल्यवान कौशल और ज्ञान भी प्रदान कर सकते हैं।

**प्रभावी ढंग से संचार करें:** सफल स्वयंसेवा के लिए अच्छा संचार आवश्यक है। स्वयंसेवक समन्वयक या टीम लीडर के साथ अपनी उपलब्धता, कौशल और अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट और ईमानदार रहें। अपने स्वयंसेवक अनुभव के दौरान संचार की खुली लाइनें रखें, ज़रूरत पड़ने पर प्रश्न पूछें और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करें।

**विश्वसनीय और प्रतिबद्ध रहें:** स्वयंसेवा में अक्सर समय और ऊर्जा की प्रतिबद्धता शामिल होती है। समय पर उपस्थित होकर और अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपने कर्तव्यों को पूरा करके विश्वसनीय बनें। यदि आप शेड्यूलिंग विवादों या अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके संगठन से संपर्क करें। निरंतरता और विश्वसनीयता एक स्वयंसेवक के रूप में विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण करती है।

**सहानुभूति और सम्मान दिखाएँ:** आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ सहानुभूति, दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करें, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियाँ कुछ भी हों। याद रखें कि आप दूसरों का समर्थन करने और उनका उत्थान करने के लिए हैं, न कि अपने विश्वासों को आंकने या थोपने के लिए। सक्रिय रूप से सुनें, करुणा दिखाएं और विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति खुले दिमाग वाले बनें।

**स्व-देखभाल का अभ्यास करें:**

स्वयंसेवा करना भावनात्मक और शारीरिक रूप से कठिन हो सकता है, खासकर यदि आप कमजोर आबादी के साथ या उच्च तनाव वाले वातावरण में काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर ब्रेक लेकर, सीमाएं तय करके और साथी स्वयंसेवकों या पर्यवेक्षकों से समर्थन मांगकर आत्म-देखभाल को प्राथमिकता दें। अपना ख्याल रखना यह सुनिश्चित करता है कि आप लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव डालना जारी रख सकते हैं।

**चिंतन करें और सीखें:**

प्रत्येक स्वयंसेवक अनुभव के बाद, आपने क्या सीखा, क्या हासिल किया और आप कैसे सुधार कर सकते हैं, इस पर विचार करने के लिए समय निकालें। अंतर्दृष्टि और प्रतिक्रिया साझा करने के लिए एक जर्नल रखने या अन्य स्वयंसेवकों के साथ संक्षिप्त सत्र में भाग लेने पर विचार करें। निरंतर सीखना और आत्म-चिंतन आपको एक स्वयंसेवक के रूप में व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से बढ़ने में मदद करता है।

**लंबी अवधि के लिए प्रतिबद्ध रहें:**

सार्थक संबंध बनाने और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए अक्सर दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। जबकि एक बार की स्वयंसेवी घटनाएं मूल्यवान हो सकती हैं, किसी ऐसे कारण या संगठन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता बनाने पर विचार करें जिसके बारे में आप भावुक हैं। आपके निरंतर प्रयासों से आपके समुदाय में अधिक प्रभाव और स्थायी परिवर्तन हो सकता है।

इन चरणों और दृष्टिकोणों का पालन करके, आप खुद को एक अच्छा स्वयंसेवक बनने के लिए तैयार कर सकते हैं और दूसरों के जीवन में सार्थक बदलाव ला सकते हैं। याद रखें कि स्वयंसेवा केवल इस बारे में नहीं है कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, बल्कि यह उस व्यक्तिगत विकास और संतुष्टि के बारे में भी है जो आप अनुभव से प्राप्त करते हैं। आपका योगदान, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, सकारात्मक परिवर्तन लाने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने की शक्ति रखता है।

यदि आप हमारी स्वयंसेवीशाला से जुड़ते हैं, तो अपना कौशल और संक्षिप्त बायोडाटा अवश्य लिखें और Indiangreenbuddy@gmail.com पर ईमेल करें। हमारी टीम आपको आपके संबंधित स्थानों के प्रमुख गैर सरकारी संगठनों या समुदाय से जुड़ने और मार्गदर्शन करने में मदद करेगी।

*डॉ अंकुर शरण*
*ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ के सह संस्थापक और प्रबंधन ट्रस्टी*

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी–18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए–4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली– 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023